



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 फरवरी, 2023 ई0 (माघ 29, 1944 शक सम्वत्) [संख्या-07

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	137-191	3075
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	35-38	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	01-02	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	177-200	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग-1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

28 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 1351/XX-1-2022-2(32)2003-एतद्वारा, भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग में पुलिस उप महानिरीक्षक, वेतन मैट्रिक्स स्तर-13ए के रिक्त 01 पद एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 85105 (Comp. No. 29197) दिनांक 21.12.2022 द्वारा सृजित 01 अस्थायी पद (कुल 02 पदों) के सापेक्ष सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं बैच वर्ष	अनुमन्यता की तिथि
1	2	3
1.	श्री दलीप सिंह कुंवर, (IPS:SPS 2009)	01.01.2023
2.	श्री ददनपाल, (IPS:SPS 2009)	01.01.2023

विज्ञप्ति/पदोन्नति

28 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 1352/XX-1-2022-2(32)2003-एतद्वारा, भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग के अधिकारी, श्री सुखबीर सिंह, IPS:SPS-2010 को चयन वेतनमान (Selection Grade) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 के पद पर सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01.01.2023 से पदोन्नति प्रदान किये जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग-1

कार्यालय आदेश

02 जनवरी, 2023 ई०

संख्या I/87492/2022-शासनादेश संख्या 3407/III-500(5).46 दिनांक 06 नवम्बर, 1946 (Manual of Government Orders के प्रस्तर-250) के प्रावधानों के अधीन श्रीमती विभा दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक का विवाह होने के उपरान्त श्रीमती विभा दीक्षित के सेवा अभिलेखों में उनका नाम 'विभा दीक्षित' के स्थान पर 'विभा पाण्डे' अंकित किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

गृह (अधिष्ठान) अनुभाग-03

अधिसूचना

नियुक्ति

18 जनवरी, 2023 ई०

संख्या 91744/XX-3 / 2023-02(06) / 2009-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा-2021 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स का स्तर-10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रु० 15600-39,100 + ग्रेड पे-रु० 5400) के पद पर इस विज्ञप्ति में अग्रेत्तर प्रस्तरों में उल्लिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1	श्री अभिनव त्यागी	श्री अंबरीश त्यागी	एच-322, रिलायंस टाउनशिप, नागोथाने, रायगढ़, महाराष्ट्र। पिन कोड-402125
2	श्री ईशान कटारिया	श्री आर०डी० कटारिया	टावर-बी-2, प्लैट नं०-1004, रेडिकोन वेदांतम, नोएडा एक्सटेंशन, सैक्टर-16 सी, उत्तर प्रदेश। पिन कोड-201301
3	श्री गौरव किरार	श्री रघुवीर सिंह	प्राइड परपल क्रोनेट, द्वितीय तल, बाटा शोरूम के ऊपर, बाणेर, पुणे, महाराष्ट्र। पिन कोड-411045

2- उक्तानुसार नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा शर्तें उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त 'उ०प्र० अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 1984'(समय-समय पर यथासंशोधित) तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित की जायेगी।

3- उक्त अभ्यर्थियों को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- अभ्यर्थियों द्वारा पत्र निर्गत होने की तिथि के 01 माह के भीतर उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून में योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। समुचित कारणों के बिना योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

5- अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों के साथ पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में योगदान प्रस्तुत किया जायेगा:-

- 1) केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
- 2) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा पत्र।
- 3) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र।
- 4) 'इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923' के प्राविधानों को पड़े जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
- 5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र।
- 6) शैक्षिक योग्यता एवं स्थाई निवास प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

5- पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने से पूर्व 'राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड' से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।

6- नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा यथानिर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण/विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा।

7- अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

25 नवम्बर, 2021 ई०

संख्या 3539/तीन-44/रा०प०/2018-19-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शा०सं०-707/XVIII(3)/2021-03(10)/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 से प्राप्त अनुमति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-6 की उपधारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-83/31-A-813-1954-Rev(A) दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्रेश कुमार, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून, जनपद हरिद्वार, तहसील लक्सर के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2556/तीन-44/रा०प०/2018-19, दिनांक 12 सितम्बर, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुये जनपद हरिद्वार की तहसील हरिद्वार परगना ज्वालापुर के ग्राम कटारपुर अलीपुर को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुये उक्त ग्राम की विज्ञप्ति को एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

विज्ञप्ति

19 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 4701/तीन-60/च०सं०/2022-23-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शा०सं०-1067/XVIII(3)/2022-03(10)/2016, दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 से प्राप्त अनुमति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र०अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-6 की उपधारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-83/31-A-813-1954-Rev(A) दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्रेश कुमार, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून, जनपद हरिद्वार, तहसील लक्सर के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-159/मु०रा०आ०/(चक)/, दिनांक 08 मई, 2003 में आंशिक संशोधन करते हुये जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर परगना मंगलौर के ग्राम सलेमपुर बक्काल को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुये उक्त ग्राम की विज्ञप्ति को एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

विज्ञप्ति

15 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 4644/तीन-22/च०सं०/2021-22-जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, हरिद्वार के पत्र संख्या-124/पे०का०, दिनांक 12 जौलाई, 2022 से की गई संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र०अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा-4 की उपधारा-(2) (क) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-3741/सी०एच०आई०ई०-454/53, दिनांक 21 नवम्बर, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके शासनादेश संख्या-1081/XVIII(3)2022-07(21)2008, दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 के अनुपालन में, मैं चन्द्रेश कुमार, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि जनपद हरिद्वार के तहसील रुड़की के नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्राम में उपर्युक्त अधिनियम के अधीन चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने में इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चकबन्दी क्रियायें की जायेगी :-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जिला
1.	कल्याणपुर उर्फ नारसन कलौ	रुड़की	मंगलौर	हरिद्वार

चन्द्रेश कुमार,
संचालक, चकबन्दी/
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01

कार्यभार प्रमाणक

21 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 233/नि०स०/अ०स०/2022-प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश सं० File No PVD 1-IAS/JAG/1/2022-XXX-1 (Computer No 44239) 1/85119/2022 देहरादून, दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 के क्रम में जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, के अनुपालन में कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान रू० 15,600-39,100 + ग्रेड पे रू० 7600/- (पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद का कार्यभार अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 के पूर्वाह्न में ग्रहण कर लिया गया है।

अवमोचक अधिकारी

—

(उमेश नारायण पाण्डेय)

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

प्रतिहस्ताक्षरित,

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)

सचिव।

वित्त अनुभाग-8

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 86152/2022/07(100)/XXVII(8)/2008-मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के संस्तुति पत्र सं०-5524/XIII-f-7/Admin.A/2004, दिनांक 16.12.2022 के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा-54 की उपधारा (2)(क) एवं उपधारा (4)(क)के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री भलिक मजहर सुल्तान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा को अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

कार्यालय ज्ञाप

29 दिसम्बर, 2022 ई0

संख्या 675/VII-A-2/2022/17-उद्योग/2013-राज्यपाल, औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1675/VII-A-2/2021/17-उद्योग/2013-दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के क्रम में राज्य में लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन हेतु प्रख्यापित मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021 के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित परिचालन दिशानिर्देश बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2021 परिचालन दिशानिर्देश, 2022

अध्याय-एक

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ एवं लागू होना
- (1) इन दिशानिर्देशों का संक्षिप्त नाम मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2021 परिचालन दिशानिर्देश, 2022 है। (संक्षेप में एमआईआईपी परिचालन दिशानिर्देश 2022)
 - (2) यह दिशानिर्देश मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2021 प्रख्यापित होने की तारीख से अर्थात् 31 दिसम्बर, 2021 से प्रभावी होंगे तथा नीति की वैधता अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे।

- (3) पात्र उद्यम/इकाइयां मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति, 2021 के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा के प्रारम्भ करने के दिनांक से नीति की वैधता अवधि के भीतर अधिकतम पांच वर्षों के लिए प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण: मेगा औद्योगिक और निवेश नीति-2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अन्तर्गत स्थापित/स्थापनाधीन नयी तथा विस्तारीकरण की परियोजनाओं/इकाईयों को उक्त नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 640/2016/VII-1/17-उद्योग/2013 दिनांक 28.07.2016 से प्रख्यापित मेगा औद्योगिक और निवेश नीति के परिचालन दिशा-निर्देश-2016 के प्राविधानों के अनुसार ही अनुमन्य होगा।

2. परिभाषाएँ
- (क) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने से अभिप्रेत है:
 - (i) नई इकाई के लिए वह तिथि जिस पर इकाई तैयार उत्पादों का पहला बिक्री बिल जारी करती है।
 - (ii) विस्तार के लिए निवेश करने वाली मौजूदा इकाई के लिए, वह तारीख जिस पर इकाई विस्तार के पूरा होने के बाद तैयार उत्पाद का पहला बिक्री बिल जारी करती है।

- (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकारी अथवा अभिकरण अथवा प्रतिनिधि, जिन्हें नीति के क्रियान्वयन के लिए इन दिशानिर्देशों के अधीन विशिष्ट प्राधिकार सौंपे गये हैं, अभिप्रेत है ;
- (ग) "संवितरण अभिकरण" से उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (संक्षिप्त में सिडकुल) या ऐसे अन्य अभिकरण/विभाग जिन्हें समय-समय पर इस नीति के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान/वित्तीय प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु अधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है ;
- (घ) "विद्युत अधिभार" का अर्थ वही होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश विद्युत इलेक्ट्रीसिटी (अधिभार) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 में परिभाषित किया गया है।
- (ङ) "मौजूदा औद्योगिक इकाई" से ऐसी औद्योगिक इकाई, अभिप्रेत है जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 से पहले स्वनिर्मित उत्पाद के व्यवसायिक उत्पादन तथा सेवा का प्रचालन कर रही हो तथा जिसने इकाई के विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण / विविधीकरण के लिए www.investuttarakhand.com पोर्टल पर संयुक्त आवेदन प्ररूप-1 पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर राज्य/जिला प्राधिकृत समिति के अनुमोदन से परियोजना के विस्तार के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की हो ;
- (च) औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदा/विशेष औद्योगिक संपदा या कोई अन्य अधिसूचित/चिन्हित भूमि से अभिप्रेत है:
- (i) सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक पार्क/आस्थान।
 - (ii) राज्य औद्योगिक विकास विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थान।
 - (iii) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निजी औद्योगिक क्षेत्र / आस्थान / विशेष औद्योगिक आस्थान ;
 - (iv) राज्य में संबंधित विनियमित क्षेत्रों के जोनल मास्टर प्लान में औद्योगिक/वाणिज्यिक/और चिन्हित की गई सेवा गतिविधियों के उपयोग के लिए अधिसूचित और चिन्हित भूमि ;
 - (v) पात्र गतिविधियों के लिए विनियमित क्षेत्रों में अधिसूचित अथवा चिन्हित ऐसी भूमि, जिस पर परियोजना की स्थापना के लिए सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन मानचित्र को अनुमोदित कर दिया गया है ;
 - (vi) उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 143 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित किया गया हो ;
- (छ) "औद्योगिक/सेवा क्षेत्र" की इकाई से ऐसी कोई औद्योगिक इकाई/परियोजना अथवा पात्र सेवा क्षेत्र का उद्यम अभिप्रेत है जो कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अर्थात् एक पंजीकृत उद्यम हो तथा जिसकी स्थापना के लिए भारत सरकार, उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग (औद्योगिक सहायता सचिवालय) में आईईएम

- पार्ट-ए (आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र) दाखिल कर अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी हो ;
- (ज) "कार्यान्वयन एजेंसी" से उत्तराखण्ड सरकार का औद्योगिक विकास विभाग या महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड का कार्यालय, जिसे नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, अभिप्रेत है ;
- (झ) "लार्ज प्रोजेक्ट" अथवा "लार्ज इकाई" से ऐसी नयी अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाई अभिप्रेत है, जिसके द्वारा भूमि, भवन तथा प्लांट व मशीनरी या उपस्करों में रु. 50 करोड़ से रु. 75 करोड़ तक का स्थिर पूंजी निवेश किया गया हो ;
- (ञ) "मेगा प्रोजेक्ट" अथवा "मेगा इकाई" से ऐसी नयी अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाई अभिप्रेत है, जिसके द्वारा भूमि, भवन तथा प्लांट व मशीनरी या उपस्करों में रु. 75 करोड़ से रु. 200 करोड़ तक का स्थिर पूंजी निवेश किया गया हो ;
- (ट) "विनिर्माणक उद्यम" से औद्योगिक उपक्रम या कोई अन्य प्रतिष्ठान, जो भी नाम से जाना जाता है, किसी भी तरह से माल के निर्माण या उत्पादन में लगा हुआ है, जो उद्योगों (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951) (1951 का 55) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से सम्बन्धित है और जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में विनिर्माणक उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो, अभिप्रेत है ;
- (ठ) "नई औद्योगिक इकाई" से वह औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है जिसने 31 दिसम्बर, 2021 से पहले लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजना की स्थापना के लिए एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत www.investuttarakhand.com पोर्टल पर संयुक्त आवेदन प्ररूप-1 पर आवेदन कर राज्य/जिला प्राधिकृत समिति के अनुमोदन से परियोजना की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की हो ;
- (ड) "नई परियोजना/इकाई" से वह परियोजना/इकाई जिसने मेगा औद्योगिक और निवेश नीति-2021 (एमआईआईपी-2021) की वैधता अवधि के दौरान स्थापित होकर अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है ;
- (ढ) "नोडल अभिकरण" से उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में राज्य उद्योग मित्र प्रकोष्ठ अथवा एकल खिड़की व्यवस्था प्रकोष्ठ अभिप्रेत है, जिसे इस नीति के अन्तर्गत आवेदनों को प्राप्त करने, समुचित स्तर पर आवेदनों की संवीक्षा/परीक्षण तथा स्वीकृति के लिए अग्रसारित/प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया हो। उद्योग निदेशालय या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी नोडल अभिकरण के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ;
- (ण) "नीति" से मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021 अभिप्रेत है ;

- (त) "संवीक्षा समिति" से इन दिशानिर्देशों के संलग्नक परिशिष्ट-क में यथाउल्लिखित दिशानिर्देश और नीति के अधीन प्राप्त आवेदनों और दावों की संवीक्षा के लिए गठित समिति अभिप्रेत है।
- (थ) "सेवा उद्यम" से सेवायें प्रदान करने या उपलब्ध कराने में लगे हुए ऐसे उद्यम, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 में परिभाषित किया गया हो और यह गतिविधि इस नीति के अन्तर्गत पात्र सेवा गतिविधियों में सम्मिलित हो, अभिप्रेत है ;
- (द) "स्टाम्प अधिभार" से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन देय स्टाम्प अधिभार के रूप में परिभाषित अधिभार अभिप्रेत है ;
- (ध) "राज्य वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी)" से उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या-6 वर्ष, 2017) की धारा 9 के अधीन उदग्रहीत राज्य वस्तु और सेवा कर अभिप्रेत है ;
- (न) "राज्य स्तरीय समिति" से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (जिसे यहां आगे एकल खिड़की अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित समय-समय पर यथासंशोधित सम्बन्धित नियमों अथवा नीति के अधीन लाभ की स्वीकृति के लिए समय-समय पर यथाविहित कोई अन्य समिति के रूप में यथाविहित राज्य स्तरीय समिति अभिप्रेत हैं।
- (प) "पर्याप्त विस्तार" से क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण तथा अभिनवीकरण के प्रयोजन के लिए मौजूदा औद्योगिक इकाई/परियोजना की भूमि, भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी / उपस्करों में, लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम अचल पूंजी निवेश की सीमा, यथा: रु. 50 करोड़, रु. 75 करोड़, रु. 200 करोड़ तथा रु. 400 करोड़ या उससे अधिक स्थिर पूंजी निवेश की अभिवृद्धि अभिप्रेत है ;
- (फ) "सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट" अथवा "सुपर अल्ट्रा मेगा इकाई" से ऐसी नयी अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाई अभिप्रेत है, जिसके द्वारा भूमि, भवन तथा प्लांट व मशीनरी या उपस्करों में रु. 400 करोड़ से अधिक का स्थिर पूंजी निवेश किया गया हो ;
- (ब) "अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट" अथवा "अल्ट्रा मेगा इकाई" से ऐसी नयी अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाई अभिप्रेत है, जिसके द्वारा भूमि, भवन तथा प्लांट व मशीनरी या उपस्करों में रु. 200 करोड़ से रु. 400 करोड़ तक का स्थिर पूंजी निवेश किया गया हो ;

3. पात्रता मानदण्ड

- (क) इस दिशा-निर्देश के पैरा-2(अ) में चिन्हित नई औद्योगिक इकाइयों/गतिविधियों या मौजूदा इकाइयों/गतिविधियों, जो निर्दिष्ट/परिभाषित क्षेत्र/आस्थान/भूमि में स्थापित हों अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण कर रही हैं, इस नीति के अध्याधीन रहेंगी।
- (ख) केवल नीति के अन्तर्गत चिन्हित वह नई औद्योगिक इकाई/परियोजना/सेवा उद्यम या मौजूदा इकाई, जो इकाई की स्थापना/विस्तारीकरण के लिए पचास करोड़ रु0 से अधिक का पूंजी

निवेश कर रही हैं, इस नीति के अन्तर्गत आच्छादित रहेगी और मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021 में प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों और रियायतों का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

- (ग) अचल पूंजी निवेश की गणना के लिए नई परियोजना/इकाई के मामले में अचल पूंजी परिसंपत्ति के अलावा भूमि का मूल्य और भूमि विकास लागत (जैसा कि वास्तव में भुगतान किया गया / भुगतान किया जाना आवश्यक है) को जोड़ा जा सकता है, जो प्रत्येक 50 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के लिए 10 एकड़ भूमि की अधिकतम सीमा के अधीन है।
- (घ) मौजूदा इकाई के विस्तार के मामले में, गणना में केवल अतिरिक्त पूंजी निवेश (भूमि, भवन और संयंत्र और मशीनरी) को ध्यान में रखा जाएगा। मौजूदा इकाई के विस्तारित हिस्से के लिए इस नीति के अन्तर्गत सभी लाभ, प्रोत्साहन, रियायतें मौजूदा इकाई के विस्तार के प्रत्येक चरण पर लागू होंगे। इस नीति की वैधता अवधि के दौरान संबंधित विस्तारित चरणों के पहले वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से लाभ, प्रोत्साहन और रियायतों पर विचार किया जाएगा।
- (ङ) पूंजी निवेश की गणना में भूमि, भवन, नए संयंत्र और मशीनरी, उपकरण, घटक, मोल्ड, ड्राई, जिप्स और वास्तविक सम्पत्ति (उपभोग्य, डिस्पोजेबल या राजस्व प्रभार्य वस्तुओं को छोड़कर) इकाई में किया जाने वाला अचल निवेश शामिल होगा, जो मूल रूप से इकाई के संचालन के लिए आवश्यक है।
- (च) संयंत्र और मशीनरी से स्थल पर स्थापित नए खरीदे गये औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी अभिप्रेत है तथा इसमें अन्यत्र से विस्थापित/रिसाइकिल/रिफरबिशड संयंत्र और मशीनरी सम्मिलित नहीं हैं।
- (छ) राज्य/केन्द्रीय सरकार/विदेशी अभिकरण के अधीन किसी विभाग/अभिकरण से ऐसी इकाईयां जो पूर्व से ही अनुदान /प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं, इस नीति के अधीन समान प्रकृति के प्रोत्साहन को पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

4. पात्रता प्रमाण पत्र

- (क) पात्रता प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसे इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। इसे सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि तथा यह सुनिश्चित करने के पश्चात जारी किया जायेगा कि इकाई पात्रता के लिए सभी मानदंड पूरा करती है।
- (ख) नीति के अन्तर्गत चिन्हित औद्योगिक इकाई/उद्यम वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ करने के दिनांक से 90 दिन के भीतर विहित प्रारूप पर वांछित दस्तावेजों/अभिलेखों सहित ऑनलाइन नामित नोडल अभिकरण के प्राधिकृत अधिकारी को पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगी।
- (ग) पात्रता प्रमाण पत्र हेतु सम्बन्धित प्राधिकारी को ऑनलाइन विहित आवेदन पत्र के प्रारूप पर आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र की मुद्रित तीन प्रतियां अपेक्षित अभिलेखों सहित नोडल अभिकरण को प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए प्रस्तुत की जायेंगी।
- (घ) नोडल एजेंसी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि शुरू में आवेदन पत्र की

जांच करेंगे कि आवेदन पत्र ठीक से भरा गया है और क्या आवश्यक रिकॉर्ड आदि आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं तथा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए पंजिका में इसे दर्ज करेंगे। उसके बाद आवेदन पत्र आवेदन की जांच/परीक्षा के लिए वितरण एजेंसी सिडकुल को अग्रेषित किया जाएगा। संवितरण एजेंसी सिडकुल मुख्य रूप से आवेदन और उसके रिकॉर्ड की जांच करेगी और जांच के बाद आवेदन को संवीक्षा समिति के समक्ष अंतिम सिफारिश के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित संबंधित इकाई को वापस कर दिया जाएगा।

- (ब) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी।
- (च) नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र की प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी। राज्य स्तरीय समिति से पात्रता प्रमाण पत्र के आवेदन पर अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त नोडल अभिकरण का प्राधिकृत अधिकारी एक सप्ताह के भीतर विहित प्रारूप में पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा।
- (छ) मौजूदा इकाईयों के विस्तार के मामलों में विस्तारीकरण से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख, पूंजी निवेश, रोजगार तथा उत्पादित उत्पाद/प्रदत्त सेवा का विवरण (उत्पादन क्षमता सहित) विस्तार के पश्चात होने वाले पूंजी निवेश, रोजगार सृजन, प्रस्तावित उत्पाद/सेवा (उत्पादन क्षमता सहित), उद्यम रजिस्ट्रेशन अथवा आईईएम पार्ट-बी तथा पार्ट-ए की प्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगी।
- (ज) विस्तारीकरण के अधीन विद्यमान इकाई के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन प्रारूप के साथ चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित प्लान्ट व मशीनरी/उपस्कर तथा भवन के आंकलन तथा पूंजी निवेश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। विस्तारित प्रयोजन के लिए इकाई के पूंजी निवेश का आंकलन विस्तारीकरण के पश्चात प्रस्तावित उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन/प्रदत्त सेवा के प्रचालन की तारीख तक किये गये पूंजी निवेश के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
- (झ) पात्रता प्रमाण पत्र के आवेदन के प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को गुण दोष के आधार पर राज्य स्तरीय समिति मर्सित करने की अनुमति दे सकेगी।
- (ञ) जब तक राज्य स्तरीय समिति किसी दावे को अनुमोदित करने, नीति के अधीन किसी प्रोत्साहन के लिए कोई अधिकार या दावे की स्वीकृति की अनुशंसा नहीं करती, तब तक यह नहीं समझा जायेगा कि इकाई नीति की शर्तों को पूर्ण करती है।
- (ट) सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा नीति के अधीन जारी किए गये पात्रता प्रमाण पत्र के बिना नीति के अंतर्गत किसी प्रोत्साहन के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकेगा और सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के

लिए पात्रता प्रमाण पत्र की वास्तविक शर्तों का अनुपालन इकाई को करना होगा।

(व) क्रियान्वयन अभिकरण के निर्णय ऐसे निर्देशों के अधीन जैसा सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किये जायें, के अध्यक्षीन अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

(झ) पात्रता प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के पश्चात् नीति के अधीन कोई इकाई सभी प्रकार के रियायतों, प्रोत्साहनों, सहायकी (सब्सिडी), प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने के लिए अर्ह हो जायेंगे।

5. अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र (पीईसी)

(क) अनंतिम पात्रता प्रमाण ऐसा प्रमाण पत्र है, जिसे इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई इकाई की स्थापना अथवा मौजूदा इकाई के विस्तारीकरण के लिए वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा प्रचालन करने से पूर्व सिडकुल से भूमि दरों में छूट/रियायत तथा लीज अथवा क्रय की गयी भूमि के निबन्धन में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क प्रभार की प्रतिपूर्ति का दावा करना हो।

(ख) मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021 के अधीन अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित इकाई विहित प्रारूप पर अपेक्षित अभिलेखों तथा प्रमाण पत्रों के साथ नोडल अभिकरण को एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत नई परियोजना की स्थापना/मौजूदा परियोजना के विस्तारीकरण के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(ग) अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के बाद आवेदन पत्र की मुद्रित/कागजी तीन प्रतियां अपेक्षित अभिलेखों सहित 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित नोडल अभिकरण के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

(घ) नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और सम्बन्धित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि की जायेगी। नोडल अभिकरण आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति की संवीक्षा हेतु सिडकुल को अग्रसारित करेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(ङ) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी।

(च) नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र की प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी। राज्य स्तरीय समिति से पात्रता प्रमाण पत्र के आवेदन पर अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त नोडल अभिकरण का प्राधिकृत अधिकारी एक सप्ताह के भीतर विहित प्रारूप में अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

- (ख) अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, नीति के अन्तर्गत एक इकाई भूमि दरों में सिडकुल को रियायत/छूट के लिए आवेदन करने तथा स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी।
- (ज) नई इकाई की स्थापना या मौजूदा इकाई के विस्तार के लिए आईईएम पार्ट-ए की पावती सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार तथा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (औद्योगिक सहायता सचिवालय) भारत सरकार या सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सक्षम प्राधिकारी से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।
6. सिविल कार्यों और संयंत्र तथा मशीनरी के अर्ह/अनर्ह सामग्री
- (क) अर्ह सिविल कार्य:- विनिर्माण प्रक्रिया/सेवाएं उपलब्ध कराने से सीधे जुड़े निम्नलिखित सिविल कार्य अर्ह सिविल कार्य के रूप में विचार के लिए अर्ह माने जायेंगे:-
- (i) विनिर्माण और आवश्यक सहायक प्रक्रियाओं में सीधे सम्बद्ध उपयोगिता क्षेत्रों सहित कारखाना शेड/भवन अर्थात् संयंत्र भण्डार, गुणवत्ता नियंत्रण, विद्युत कक्ष, अनुरक्षण कार्यशाला (वास्तविक अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित दरें, जो भी कम हों)।
 - (ii) प्रभावी एसआईडीए मानक के अनुसार आवश्यक आवासीय सुविधाएं जो लागू हों।
 - (iii) कारखाना परिसर पर कच्चे माल और तैयार उत्पाद के गोदाम का निर्माण (वास्तविक अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित प्रभावी दरें, जो भी कम हों)।
 - (iv) आवश्यक सिविल सन्निर्माण कार्य जैसे मशीन, उपस्कर (वास्तविक अथवा लोक निर्माण विभाग अनुसूची की प्रभावी दरें, जो भी कम हों)।
 - (v) अभियंता प्रमाण पत्र विहित जगह में प्रस्तुत किया जायेगा।
 - (vi) सिविल कार्यों की वास्तविक लागत विहित प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी।
- (ख) अनर्ह सिविल कार्य: विनिर्माण प्रक्रिया/सेवाएं उपलब्ध कराने से सीधे जुड़े निम्नलिखित सिविल कार्य अनर्ह सिविल कार्य के रूप में विचार के लिए अनर्ह माने जायेंगे (सूची सम्पूर्ण नहीं है):-
- (i) चारदीवारी तथा गेट।
 - (ii) पहुँच सड़क/आंतरिक सड़क।
 - (iii) कार्यालय भवन/कार्यालय हेतु उपयोग क्षेत्र।
 - (iv) कारखाने से अलग स्थान पर कच्चा माल/तैयार माल के भण्डारण हेतु निर्मित गोदाम।
 - (v) कोई आवासीय भवन या रेस्ट हाउस/गेस्ट हाउस।
 - (vi) जलपान गृह।
 - (vii) श्रमिक विश्राम गृह तथा श्रमिकों हेतु आवास।

- (viii) सुरक्षा/गार्ड के कमरे या बाढ़ा।
- (ix) निर्माण पुल का भार।
- (x) परामर्श शुल्क, करें इत्यादि।
- (ग) पात्र संयंत्र तथा मशीनरी:
 - (i) सीधे निर्माण प्रक्रिया से जुड़े मशीनरी/उपस्करों का प्रारम्भिक मूल्य।
 - (ii) सीधे निर्माण प्रक्रिया से जुड़े उपकरण की तरह सहायक उपकरण, जिग्स, डाइज, मोल्ड्स।
 - (iii) संयंत्र और मशीनरी सहित जुड़ी मोटरें।
 - (iv) मशीनरी/उपकरणों की स्थापना, निर्माण तथा कमीशन।
 - (v) परिवहन शुल्क, परिवर्तन बीमा, वैट/सीएसटी, उत्पादन शुल्क, प्रवेश पर कर आदि (स्वदेशी मशीनरी और उपकरणों के मामले में) का भुगतान।
 - (vi) आयात शुल्क, शिपिंग शुल्क, सीवीडी, कंटेनर हैंडलिंग शुल्क, सीमा शुल्क, निकासी शुल्क, वैट/सीएसटी भुगतान बंदरगाह से परिवहन शुल्क प्रवेश कर (आयातित मशीनरी/उपकरण के मामले में) आदि।
 - (vii) गुणवत्ता नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण और अग्निशमन उपकरण।
 - (viii) आंतरिक विद्युतीकरण, पैनल बोर्ड, समर्पित ट्रांसफार्मर, गैस उत्पादक संयंत्र, विद्युत उत्पादन सेट आदि सहित विद्युत प्रतिष्ठान।
 - (ix) उपयुक्त सभी सामग्रियों का भुगतान बैंक/मांग ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा किया जायेगा जो पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले बैंक विवरण में दर्शित होना चाहिए।
 - (x) विनिर्माण क्षेत्र में उत्थापन एवं स्थापना (Erection and Installation) सम्बन्धी प्रभारों का वास्तविक आधार पर किया गया भुगतान।
 - (xi) चार्टर्ड एकाउण्टेंट प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना।

(घ) अनर्ह संयंत्र और मशीनरी:

- (i) संयंत्र और मशीनरी सीधे निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित नहीं है।
- (ii) ईंधन, उपभोग्य, पुर्जे तथा स्टोर।
- (iii) कम्प्यूटर और कार्यालय फर्नीचर।
- (iv) वाहन।
- (v) सेकण्ड हैंड/पुरानी मशीनरी।

(vi) सुरक्षा प्रणाली से सम्बन्धित उपकरण बंद किये सर्किट और सीसीटीवी कैमरे।

(vii) स्टेशनरी सामग्री।

7. अन्य

- (क) पूंजी निवेश का विनिर्धारण: पूंजी निवेश के विनिर्धारण में उत्पन्न किसी भिन्नता के मामले में राज्य स्तरीय समिति/अनुमोदन प्राधिकारी परीक्षण करेगा और उस पर निर्णय लेगा।
- (ख) विस्तारीकरण के अधीन विद्यमान इकाई के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन प्रारूप के साथ चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित प्लान्ट व मशीनरी/उपस्कर तथा भवन के आंकलन तथा पूंजी निवेश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। विस्तारित प्रयोजन के लिए इकाई के पूंजी निवेश का आंकलन विस्तारीकरण के पश्चात प्रस्तावित उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन/प्रदत्त सेवा के प्रचालन की तारीख तक किये गये पूंजी निवेश के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
- (ग) नीति के अधीन लाभ/रियायत/प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली नई इकाईयां तथा मौजूदा विस्तारीकरण करने वाली इकाईयां वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने/सेवा के प्रचालन के छः माह के पश्चात नीति में प्रदत्त रियायतों/वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए आवेदन हेतु अर्ह होंगे।
- (घ) सिविल सन्निर्माण के साथ-साथ संयंत्र और मशीनों में निवेश की अंतिम तारीख, एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से उद्यम रजिस्ट्रेशन/आईईएम-पार्ट-बी में दर्ज वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने/सेवा प्रचालन की अंकित तिथि तक होगी।
- (ङ) संवितरण अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्धता और सरकार द्वारा स्वीकृति निधि के आवंटन के अध्याधीन राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रोत्साहन, रियायत, लाभ, प्रतिपूर्ति के सापेक्ष निधि जारी की जा रही है।
- (च) राज्य स्तरीय समिति किसी आवेदन पत्र को उसके दावे/संशोधित दावे पर संवीक्षा समिति की संस्तुति के आधार पर अथवा अन्य कतिपय वैध आधार पर अनुमोदित करने या उसे अस्वीकार करने अथवा कोई आवेदन पत्र/दावों को इस प्रयोजन के लिए जैसा कि वह ठीक समझे पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता के फलस्वरूप लंबित रख सकेगा।
- (छ) यदि इस बात की पुष्टि हो कि किसी औद्योगिक इकाई ने जाली सूचना देकर धोखे से इस नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने का प्रयास किया है अथवा यदि यह इकाई वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा प्रचालन के बाद 5 वर्ष के भीतर उत्पादन बन्द कर देती है, तो उस इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ऐसी इकाई को अनुदान अथवा प्रदत्त वित्तीय सहायता लौटाने के लिए कह सकते हैं। यह अनुदान/प्रतिपूर्ति सहायता डिजिटल भुगतान के जरिए जारी की जायेगी तथा सिडकुल लाभार्थी औद्योगिक इकाईयों से इस सम्बन्ध में एक शपथपत्र ले सकता है। स्कीम की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने

वाली लाभार्थी इकाई को वितरण से पूर्व औद्योगिक इकाई और संवितरण अभिकरण सिडकुल के बीच एक अनुबन्ध पत्र भी निष्पादित किया जायेगा।

(ज) सम्बन्धित प्राधिकारी इकाई द्वारा त्रुटि से उपभोग किए गये लाभों को 30 दिन की अवधि के भीतर वापस करने के लिए कह सकेगा। यदि इकाई ऐसा करने में असफल रहती है तो प्राधिकारी धनराशि के साथ-साथ उस पर ब्याज और विधि की अधीन यथा अनुज्ञेय ऐसे दण्डात्मक कार्यवाही के साथ-साथ वसूली हेतु सक्षम विधि के न्यायालय में विधिक कार्यवाही कर सकेगा।

(झ) भूमि के आवंटन अथवा अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र अथवा पात्रता प्रमाण पत्र की जारी करने की तारीख जो भी पहले हो, से तीन वर्ष की अवधि के भीतर यदि कोई इकाई वाणिज्यिक उत्पादन करने में असफल रहती है तो नीति के अंतर्गत दिये गये लाभों को वापस लिया जा सकेगा। वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से यदि कोई इकाई लगातार तीन वर्षों के उत्पादन के बाद बंद हो जाती है तो सम्बन्धित समिति द्वारा इस प्रकार अनुमोदित अनुदान/सब्सिडी की धनराशि सम्बन्धित इकाई को उनके बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जारी कर दी जायेगी।

(ञ) सभी पात्र इकाईयां विहित प्रारूप के अनुसार यह विवरण देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी कि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सूचनाएं सही हैं।

8. उपांतरण / संशोधन इत्यादि की शक्ति

(क) राज्य सरकार को किसी भी समय लोक हित में दिशानिर्देशों के किसी भाग में कोई विस्तार, उपांतरण या निरसन करने का अधिकार होगा।

(ख) राज्य सरकार समुचित मामलों में सावधानीपूर्वक लाभ और हानि पर विचार करते हुए इस नीति के किसी विशेष उपबंध के लागू होने और लागू नहीं होने के संबंध में रियायत दे सकेगी।

(ग) राज्य सरकार यदि वह ऐसा चाहे तो समुचित मामलों में सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात नीति के अधीन किसी प्रोत्साहन/लाभ को उपांतरित करने या कोई शर्त विस्तारित करने या अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगी।

9. विविध

(क) यदि इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित होगा तो औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने के लिए अधिकृत होगा।

(ख) औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन किसी मामले में कोई अस्पष्टता हो तो वह किसी उपबंध का सही रूप में निर्वचन करने की अधिकारिता होगी।

10. ऋणों का सुधार

नीति के अधीन अनुदान की धनराशि के प्रशमन में अभिलेखों पर दर्शित किसी त्रुटि को ठीक करने की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी अपने आदेश से ऐसी इकाई को अनुदान वितरित कर सकेगी और अधिक भुगतान की वसूली यदि कोई हो 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूल कर सकेगी। इस योजना के अधीन दिये गये लाभ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि के पश्चात जहां पूर्ण रूप से लाभों का उपभोग

किया जा चुका हो, के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

11. अपील
- (क) राज्य स्तरीय समिति को सम्बन्धित विभाग/क्रियान्वयन अभिकरण/संवितरण अभिकरण के सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध किसी अपील को सुनने और उसके निस्तारण की शक्ति होगी।
 - (ख) राज्य स्तरीय समिति के किसी आदेश/निर्णय के विरुद्ध कोई अपील राज्य सरकार को की जा सकेगी।
 - (ग) अपील के लिए आवेदन पत्र निर्णय को सूचित करने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जा सकेगी।
12. स्पष्टीकरण/संशोधन/शोधन जारी करने का प्राधिकरण
- (क) उत्तराखण्ड सरकार में लोक हित में जब और जैसा आवश्यक हो नीति को संशोधित/उपांतरित/स्पष्टता करने का अधिकार होगा। यद्यपि इस नीति से संलग्न प्रारूप नीति के क्रियान्वयन में सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जब और जैसे आवश्यक हों, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उपांतरित, परिवर्तित, विस्तारित अथवा निरसित किए जा सकेंगे।
 - (ख) उत्तराखण्ड सरकार के औद्योगिक विकास विभाग में किसी मामले में कोई अस्पष्टता हो तो वह किसी उपबंध का सही रूप में निर्वचन करने की अधिकारिता होगी।
 - (ग) राज्य सरकार समुचित मामलों में सावधानीपूर्वक लाभ और हानि पर विचार करते हुए इस नीति के किसी विशेष उपबंध के लागू होने और लागू नहीं होने के संबंध में रियायत दे सकेगी।
 - (घ) औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के पास इन दिशानिर्देशों/नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण मांगे जाने पर आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।
 - (ङ) औद्योगिक विकास विभाग को किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान की सही व्याख्या करने का अधिकार होगा।

अध्याय-दो

पात्र इकाईयों को लाम/रियायतें/प्रोत्साहन

13. सिडकुल द्वारा भूमि का आवंटन
- (क) इन उपबंधों के अधीन भूमि का आवंटन एच्छिक आवेदकों को समय-समय पर अभिनिश्चित दिशानिर्देशों तथा सिडकुल के प्रभावी दरों के अनुसार एकल खिड़की व्यवस्था के अधीन सिडकुल द्वारा किया जायेगा।
- (ख) इस नीति के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर भूमि आवंटन में सिडकुल के प्रभावी दरों पर लार्ज प्रोजेक्ट हेतु 15 प्रतिशत, मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु 25 प्रतिशत तथा अल्ट्रा मेगा व सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु 30 प्रतिशत की विशेष छूट/रियायत दी जायेगी।
- (ग) इस नीति के अधीन सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत भूमि के आवंटन के समय भुगतान किया जायेगा तथा शेष धनराशि 5 वर्ष की समान किरस्तों पर निर्धारित ब्याज सहित देय होगी।
14. पात्र लार्ज/मेगा/अल्ट्रा मेगा/सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए नीति के अधीन प्रोत्साहन और अन्य रियायतें
- (i) पात्र इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के दिनांक से आगामी पांच वर्ष तक सावधि ऋण पर सात प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी अधिकतम वार्षिक सीमा लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा व सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए क्रमशः रु. 25 लाख, रु. 35 लाख, रु. 50 लाख व रु. 75 लाख होगी।
- (ii) तैयार माल की बी2सी बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के समायोजन के पश्चात देय कुल शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा/मात्रा निम्नानुसार होगी: -
- (क) लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से आगामी 5 वर्ष हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एसजीएसटी कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 30 प्रतिशत।
- (ख) मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स/सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एसजीएसटी कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

स्पष्टीकरण:

- (i) माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आईटीसी0 के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इस योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत दिए गए ऐसे एसजीएसटी कर के भाग की प्रतिपूर्ति की

जायेगी जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी.टू.सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो।

- (ii) एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ केवल विनिर्माण उद्योगों को ही अनुमन्य होगा।
- (iii) पात्र उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक देय विद्युत बिल में रु. 1.00 प्रति यूनिट की दर से अधिकतम नियत सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी। विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा लार्ज प्रोजेक्ट्स हेतु रु. 50 लाख प्रतिवर्ष, मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रु. 75 लाख प्रतिवर्ष, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रु. 1 करोड़ प्रतिवर्ष तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रु. 1.50 करोड़ प्रतिवर्ष होगी।
- स्पष्टीकरण: नीति के अन्तर्गत चिन्हित पात्र सेवा गतिविधियों में सम्मिलित यथा: होटल, रिसॉर्ट, रोप-वे, मोटेल, हॉस्पिटल आदि को विद्युत बिल में देय प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- (iv) पात्र उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक उत्पादन कार्य में उपभोग किये गये विद्युत बिल पर देय/भुगतान की गयी इलेक्ट्रिक ड्यूटी की पात्र उद्यमों को शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- स्पष्टीकरण: नीति के अन्तर्गत चिन्हित पात्र सेवा गतिविधियों में सम्मिलित यथा: होटल, रिसॉर्ट, रोप-वे, मोटेल, हॉस्पिटल आदि को भुगतान की गयी इलेक्ट्रिक ड्यूटी पर प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- (v) भूमि क्रय विलेख पत्र तथा लीज डीड के निष्पादन में देय स्टाम्प शुल्क प्रभार पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।
- (vi) भूमि के विक्रय विलेख पत्र तथा लीज डीड के पंजीयन में देय प्रति रु. 1000 पंजीकरण शुल्क के सापेक्ष रु. 999 की प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।
- (vii) ईटीपी संयंत्र की स्थापना पर 30 प्रतिशत, अधिकतम रूपया 50 लाख तक का पूंजीगत उपादान देय होगा।
- (viii) बृहत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु (पे-रॉल सहायता) (Payroll assistance): (पे-रॉल सहायता) (Payroll assistance) की अनुमन्यता हेतु लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 50, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 100, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 200 तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 400 लोगों को नियमित रोजगार की न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा होगी। जिन उद्यमों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नियमित कर्मचारी कार्यरत होंगे, को निर्दिष्ट सीमा के अतिरिक्त नियोजित कर्मचारियों पर रु. 500/- प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से आगामी 5 वर्ष तक उपादान के रूप में पे-रॉल असिस्टेंस सहायता दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु पे-रॉल असिस्टेंट सहायता रु. 700/- प्रतिमाह प्रति कर्मचारी होगी।

अध्याय-तीन

लामों के उपबन्ध, प्रक्रियाएं और संवितरण

15. ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता:

(क) ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के लिए उपबन्ध।

(i) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य योजना/लाम के अधीन कोई समान लाम अथवा प्रोत्साहन अथवा सहायकी (सब्सिडी) प्राप्त कर रही इकाईयां इस योजना के अधीन लाम प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगी।

(ii) ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण के लिए लिए गए सावधि ऋण पर स्वीकार्य होगी। नीति के लागू होने से पूर्व लिया गया कोई भी सावधि ऋण, जिसकी पहली किश्त इस नीति के लागू होने से पूर्व संवितरित की जा चुकी हो, पर ब्याज प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति सहायता का लाम अनुमन्य नहीं होगा।

(iii) ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा ऋण के पुनः भुगतान की अवधि तक जो भी पहले हो, अनुज्ञेय होगी। ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता की अवधि प्रथम किश्त के संवितरण की तारीख से अनुज्ञेय अवधि तक गणना में ली जायेगी।

(iv) ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता ऐसे इकाईयों को दी जायेगी जिन्होंने नियमित रूप से वित्तीय संस्थाओं/बैंक को किश्त और ब्याज का भुगतान किया हो। यदि इकाईयां इसमें असफल होंगी तो असफलता अवधि के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता नहीं दी जायेगी और उपर्युक्त उपखण्ड (iii) में यथाउल्लिखित पांच वर्ष की अवधि से ऐसी असफलता अवधि घटा दी जायेगी।

(ख) ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के दावे हेतु प्रक्रिया:

(i) नीति के अधीन ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपभोग करने के इच्छुक पात्र इकाईयों को एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप पर अपेक्षित अभिलेखों के साथ ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता का दावा प्रस्तुत करना होगा। ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था का इस आशय का प्रमाण पत्र कि इकाई द्वारा नियमित रूप से मूलधन तथा ब्याज का पुनर्भुगतान कर रहे हैं, प्रस्तुत करना होगा। बैंक मूलधन/ब्याज के पुनर्भुगतान में किसी असफलता के बारे में भी प्रमाण पत्र में उल्लेख करेंगे। ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के प्रतिपूर्ति के दावे हेतु प्रथम आवेदन पत्र वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात 45 दिन के भीतर किया जायेगा। तत्पश्चात के दावे त्रैमासिक आधार पर त्रैमास समाप्ति के बाद 45 दिन के अन्दर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रित तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडकुल को अग्रसारित किया जायेगा। सिडकुल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(iii) जहां उपखण्ड (i) में यथाउपबन्धित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्षित किया जा सकेगा।

- (iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।
- (v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।
- (vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरन्त पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।
- (ग) ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता का संवितरण करने के लिए प्रक्रिया:
- (i) ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता का संवितरण केवल वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के पश्चात किया जायेगा।
- (ii) नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति से सूचना प्राप्त होने पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्याधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और स्वीकृत धनराशि त्वरित रूप से सम्बन्धित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

16. विद्युत सहायता/विद्युत देयक सहायकी (सब्सिडी)

(क) विद्युत सहायता के लिए उपबंध

- (i) पात्र इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात आगामी पांच वर्षों के लिए यह सहायता दी जायेगी।
- (ii) लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात आगामी पांच वर्षों तक उत्पादन कार्य में उपभोग की गयी विद्युत के बिलों पर रु. 1 प्रति यूनिट की दर से अधिकतम निर्दिष्ट सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी। विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा लार्ज प्रोजेक्ट्स हेतु रु. 50 लाख प्रतिवर्ष, मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रु. 75 लाख प्रतिवर्ष, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रु. 1 करोड़ प्रतिवर्ष तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रु. 1.50 करोड़ प्रतिवर्ष होगी।
- (iii) पात्र विनिर्माणक इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात आगामी पांच वर्ष तक विद्युत अधिभार का शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगी।
- (iv) भुगतानित विद्युत अधिभार तथा उपभोग की गई विद्युत यूनिट पर एक रुपया प्रति की प्रतिपूर्ति केवल विनिर्माण/उत्पादन अथवा उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए जो कि इकाईयों को औद्योगिक प्रयोग के लिए दिये गये एकल संयोजनों पर लागू होगी।
- (ख) विद्युत सहायता के दावे हेतु प्रक्रिया:
- (i) विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता तथा विद्युत अधिभार की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र इकाईयां विहित प्रारूप पर नोडल अभिकरण के समक्ष ऑनलाइन आवेदन करेंगे। पात्र इकाई वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के पश्चात 45 दिन के भीतर अपना प्रथम दावा प्रस्तुत करेगी। तत्पश्चात त्रैमासिक आधार पर त्रैमास समाप्ति के उपरान्त 45 दिन के भीतर दावे प्रस्तुत किये जायेंगे।

- (ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रित तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडकुल को अग्रसारित किया जायेगा। सिडकुल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।
- (iii) जहां उपखण्ड (i) में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्षित किया जा सकेगा।
- (iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।
- (v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।
- (vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई विद्युत सहायता/विद्युत देयक सहायकी के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरन्त पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।
- (ग) विद्युत सहायता से संवितरण की प्रक्रिया:
नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अधधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

17. स्टाम्प अधिभार:

- (क) स्टाम्प अधिभार छूट/प्रतिपूर्ति के लिए उपबंध।
पात्र इकाईयों को भूमि क्रय/भूमि पट्टे के निष्पादन पर स्टाम्प अधिभार के भुगतान की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (ख) स्टाम्प अधिभार छूट के लिए प्रक्रिया:
- (i) इस नीति के अधीन विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण के लिए अथवा नई इकाई के स्थापना के लिए पात्र इकाईयां विहित प्रारूप में "स्टाम्प अधिभार के प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन" प्रारूप में सम्यक रूप से पूर्ण

- भरा गया आवेदन पत्र नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करेगा। विलेख के निष्पादन के पश्चात 45 दिन के भीतर प्रतिपूर्ति सहायता का दावा अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जायेगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- (ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रित तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडकुल को अग्रसारित किया जायेगा। सिडकुल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।
- (iii) जहां उपखण्ड (i) में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्षित किया जा सकेगा।
- (iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।
- (v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।
- (vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई स्टाम्प अधिभार छूट/प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरन्त पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।
- (ग) भुगतानित स्टाम्प अधिभार की प्रतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया:
नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्याधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

18. निबन्धन शुल्क की प्रतिपूर्ति:

(क) निबन्धन शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए उपबंध:

इस नीति के अधीन पात्र इकाई को क्रय विलेख पत्र/पट्टा विलेख के निबन्धन के लिए भुगतानित शुल्क के सापेक्ष प्रति रु. 1000 निबन्धन शुल्क पर रु. 999 की प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।

(ख) निबन्धन शुल्क के प्रतिपूर्ति के दावे हेतु प्रक्रिया:

- (i) भुगतानित निबन्धन शुल्क की प्रतिपूर्ति उपभोग करने के इच्छुक पात्र इकाई भूमि क्रय/भूमि विलेख के निबन्धन के 45 दिन के भीतर नोडल अभिकरण को आवेदन पत्र के तथ्यों की पुष्टि में शपथपत्र और चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित भुगतान के साक्ष्य एवं भुगतानित निबन्धन शुल्क के विवरण सहित विहित प्रारूप में "रजिस्ट्रीकरण शुल्क के प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र" में सम्यक रूप से प्रस्तुत करेगा।
- (ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडकुल को अग्रसारित किया जायेगा। सिडकुल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।
- (iii) जहां के उपखण्ड (i) में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्षित किया जा सकेगा।
- (iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।
- (v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।
- (vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरन्त पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(ग) संवितरण हेतु प्रक्रिया:

नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यक्षीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

19. ईटीपी पर पूंजीगत उपादान:

(क) ईटीपी संयंत्र की स्थापना हेतु उपादान के लिए उपबंध:

- (i) पात्र परियोजनाओं/इकाईयों को नीति के अधीन, ईटीपी संयंत्र की स्थापना लागत पर 30 प्रतिशत, अधिकतम रूपया 50 लाख की पूंजीगत उपादान सहायता दी जायेगी।
- (ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अन्य योजना/पैकेज के अधीन समान सहायकी प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति के अधीन पूंजी सहायकी के लिए अर्ह नहीं होगी।
- (iii) ईटीपी के स्थापना हेतु सहायकी ईटीपी के स्थापना से सीधे जुड़े हुए नियत पूजी निवेश पर आंगणित की जायेगी।
- (iv) पात्र इकाईयां ईटीपी संयंत्र के सफलतापूर्वक पूर्णता के पश्चात ईटीपी के स्थापना हेतु सहायकी दावा प्रस्तुत कर सकेंगे।

(ख) ईटीपी के स्थापना पर उपादान दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:

- (i) ईटीपी के स्थापना पर पूंजीगत उपादान प्राप्त करने की इच्छुक पात्र इकाई वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात 45 दिन के भीतर नोडल अभिकरण को तथ्यों की पुष्टि में बिल वाउचर्स, भुगतान के विवरण, शपथपत्र और चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित भुगतान के विवरण विहित प्रारूप में "ईटीपी हेतु सहायकी के दावों के लिए आवेदन पत्र" में प्रस्तुत करेगा।
- (ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडकुल को अग्रसारित किया जायेगा। सिडकुल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।
- (iii) जहां ऊपर उपखण्ड (i) में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्षित किया जा सकेगा।
- (iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य प्राधिकृत समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।
- (v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।
- (vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई ईटीपी के स्थापना हेतु सहायकी के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई

तथा सभी सम्बन्धितों को तुरंत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(ग) संवितरण हेतु प्रक्रिया:

नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

20. उच्च रोजगार सृजन उन्नयन के लिए पे-रौल सहायता:

(क) पे-रौल सहायता के लिए उपबंध:

(i) (पे-रौल) (Payroll assistance) सहायता की अनुमन्यता हेतु लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 50, मेगा प्रोजेक्ट के लिए 100, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 200 तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 400 लोगों को नियमित रोजगार की न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा होगी। जिन उद्यमों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नियमित कर्मचारी कार्यरत होंगे, को निर्दिष्ट सीमा के अतिरिक्त नियोजित कर्मचारियों पर रु. 500/- प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से आगामी 5 वर्ष तक उपादान के रूप में पे-रौल असिस्टेंस सहायता दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु यह दर रु. 700/- प्रतिमाह प्रति कर्मचारी होगी।

(ii) अतिरिक्त कर्मचारी से निर्दिष्ट नियोजित कर्मचारियों से अधिक कर्मचारियों की संख्या अभिप्रेत है।

(iii) केन्द्र/राज्य सरकार के किसी अन्य योजना/पैकेज के अधीन समान सहायकी उपभोग करने वाली इकाई इस नीति के अधीन पूंजी सहायकी के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) पे-रौल सहायता के दावों के लिए प्रक्रिया:

(i) पे-रौल सहायता की प्रतिपूर्ति उपभोग करने के इच्छुक पात्र इकाई निर्दिष्ट संख्या से अधिक कर्मचारियों के नियोजन के 45 दिन के भीतर नोडल अभिकरण को आवेदन पत्र तथ्यों/साक्ष्यों तथा श्रम विभाग द्वारा प्रमाणित विवरण विहित प्रारूप में 'पे-रौल सहायता के दावों के लिए आवेदन पत्र' में प्रस्तुत करेगा।

(ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडकुल को अग्रसारित किया जायेगा। सिडकुल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(iii) जहां ऊपर अध्याय-तीन के खण्ड 6(b)(i) में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्षित किया जा सकेगा।

(iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य प्राधिकृत समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

(v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।

(vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई पे-रौल सहायता के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरन्त पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(ग) संवितरण हेतु प्रक्रिया:

नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

21. एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति:

(क) एसजीएसटी के लिए उपबन्ध:

(i) औद्योगिक इकाई/परियोजना अपने उद्यम को माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत करायेगी।

(ii) स्वनिर्मित माल/वस्तु के बीटूसी विक्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के समायोजन के पश्चात देय कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा निम्नानुसार होगी:-

(क) लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से आगामी 5 वर्ष हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 30 प्रतिशत।

(ख) मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स/सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस.जी.एस.टी. कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू सी) को विक्रय किया गया हो, का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

स्पष्टीकरण:

(i) माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आईटीसी के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इस योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत दिए गए ऐसे एस.जी.एस.टी. कर के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी.टू.सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो।

(ii) एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ केवल विनिर्माण उद्योगों को ही अनुमन्य होगा।

(ख) एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया:

(i) पात्र विनिर्माणक इकाईयों द्वारा सर्वप्रथम माल और सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप मासिक/त्रैमासिक विवरणी दाखिल की जायेगी तथा विवरणी के अनुसार राज्य माल और सेवा कर (SGST) अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में

जमा की जायेगी तथा काई भी अंश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई0टी0सी0 के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इन दिशा निर्देशों के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये राज्य माल और सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) के अनतर्गत दिये गये, ऐसे एस0जी0एस0टी0 के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी टू सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो।

- (ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट संलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और संबंधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ संलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडकुल को अप्रसारित किया जायेगा। सिडकुल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।
- (iii) जहां उपखण्ड-(i) में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्षित किया जा सकेगा।
- (iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य प्राधिकृत समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।
- (v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।
- (vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरन्त पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।
- (ग) संवितरण हेतु प्रक्रिया:
नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्याधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

अध्याय चार

विभिन्न प्रोत्साहन/लाभ रियायतों के लिए आवेदन किए जाने हेतु आवेदन पत्र, प्रारूप, परिशिष्ट और संलग्नक

नीति के अधीन विभिन्न प्रोत्साहनों/लाभों/रियायतों इत्यादि के लिए आवेदन पत्र, प्रारूप, परिशिष्ट और संलग्नक निम्नवत हैं। ये क्रियान्वयन अभिकरण, नोडल अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा समय-समय पर जैसा अपेक्षित हो, यथाविहित नये प्रारूपों और ढांचों में उपांतरित अथवा परिवर्तित किये जा सकते हैं:

क्र.सं.	विवरण	प्रपत्र विवरण
1.	संवीक्षा समिति	परिशिष्ट - 1
2.	पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन (नई इकाई)	ईसी-1
3.	पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन (विद्यमान इकाई)	ईसी-1 क
4.	पात्रता प्रमाण पत्र का प्रारूप	ईसी-2
5.	अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन	पीईसी-1
6.	अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र का प्रारूप	पीईसी-2
7.	ब्याज सहायकी (सब्सिडी) के दावे हेतु आवेदन	दावा (आईएनटी)
8.	एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन	दावा (दावा)
9.	विद्युत देयक में सब्सिडी/विद्युत सहायता के दावे हेतु आवेदन	दावा (पीबीआर)
10.	स्टाम्प अधिभार की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन	दावा (एसटीडी)
11.	रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन	दावा (आरजीएफ)
12.	ईटीपी की सहायकी (सब्सिडी) के दावे हेतु आवेदन	दावा (इटीपी)
13.	पे-रौल सहाय के दावे हेतु आवेदन	दावा (पीआरए)
14.	अभियंता प्रमाण पत्रों का प्रारूप (समस्त नई इकाईयों हेतु)	अभियंता (नई इकाई)
15.	अभियंता प्रमाण पत्रों का प्रारूप (विद्यमान इकाईयों हेतु)	अभियंता (विद्यमान इकाई)
16.	सिविल कार्य की वास्तविक लागत का वक्तव्य	-
17.	संयंत्र और उपस्कर तथा अन्य सम्पत्ति पर निवेश का विवरण	-
18.	चार्टर्ड एकाउण्टेंट प्रमाण पत्र का प्रारूप (नई इकाई)	सीए-1
19.	चार्टर्ड एकाउण्टेंट प्रमाण पत्र का प्रारूप (मौजूदा विद्यमान इकाई)	सीए-2
20.	शपथ पत्र का प्रारूप	शपथ पत्र
21.	उपक्रम का प्रारूप	उपक्रम

परिशिष्ट 'क'

संवीक्षा समिति

क्र.सं.	समिति के सदस्य	पद
1.	प्रमुख सचिव/सचिव (उद्योग), उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि, जो निदेशक उद्योग के स्तर के हों।	सदस्य
3.	प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।	सदस्य
4.	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5.	निदेशक, वित्त/वित्त नियंत्रक, सिडकुल।	सदस्य
6.	महाप्रबन्धक, सिडकुल।	सदस्य सचिव

आज्ञा से,

डॉ पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 675/VII-A-2/2022/17-Industry/2013, dated December 29, 2022 for general information.

Office Memorandum

December 29, 2022

No. 675/VII-A-2/2022/17-Industry/2013--In pursuance of Office Memorandum No. 1675/VII-A-2/2021/17-Industry/2013 dated 31st December 2021, Industrial Development Section-2, Government of Uttarakhand the Governor is pleased to make the following operational guidelines for the implementation of Mega Industrial and Investment Policy, 2021 to encourage the establishment of Large, Mega, Ultra Mega and Super Ultra Mega Projects and create employment opportunities in the State :-

The Mega Industrial and Investment Policy, 2021 Operational Guidelines, 2022**Chapter- One**

1. Short Title and commencement (1) These guidelines may be called the Mega Industrial and Investment Policy Rules, 2021 Operational Guidelines, 2022 (abbreviated as MIIP Operational Guidelines 2022)

- (2) These guidelines shall be applicable from the date of issue of Mega Industrial & Investment Policy, 2021 i.e. 31st Dec, 2021 & remain in force for the entire validity period of this policy.
- (3) Eligible enterprises / units may avail the benefits, incentives & concessions as per Mega Industrial & Investment Policy, 2021 for maximum five years from the date of commencement of commercial production / service rendered within the policy validity period.

Explanation: Under the Mega Industrial & Investment Policy-2015 (as amended from time to time), the benefits of financial incentives provided in the said policy to the established / under construction new and expansion projects / units, will be permissible only as per the provisions of Mega Industrial & Investment Policy operational guidelines-2016 promulgated from Industrial Development Section-2, Government of Uttarakhand Notification No. 640/2016/VII-1/17-Udyog/2013 dated 28-07-2016.

2. Definition

- (a) Commencement of commercial production means :
 - (i) For New Unit the date on which the unit issues the first Sale bill of the finished products.
 - (ii) For an Existing Unit making investment for expansion, the date on which the unit issues the first sale bill of the finished product after completion of expansion ;
- (b) "Competent Authority" means the officer or agency or representative of the implementing agency to whom specific authority has been entrusted under these guidelines for the implementation of this policy ;
- (c) Disbursing Agency means the Uttarakhand State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited (abbreviated to SIIDCUL) or such other agencies/departments as may be authorized from time to time to disburse sanctioned grants/financial incentives under this policy ;
- (d) "Electricity Duty" means as defined in Uttar Pradesh Power Electricity (Duty) Act, 1952 (Uttarakhand Adaptation and Modification) Order, 2001 ;
- (e) "Existing industrial unit" means an industrial unit, which is already in commercial production and services rendered before the 31st December, 2021 in the state and who has obtained in-principle approval for undergoing expansion of the existing project/unit with the approval of State/District Empowered Committee by submitting an application on Common Application Form-1 on www.investuttarakhand.com Portal ;
- (f) Industrial Area/Estate/Special Industrial Estate or any other notified/identified land means :
 - (i) Industrial Area / Estate developed by SIIDCUL.

- (ii) Industrial Estate developed by State Industries Department.
- (iii) Private Industrial Area / Estate / Special Industrial Estate notified by State Government from time to time.
- (iv) Any parcel of land notified and designated for the use of Industrial / Commercial / and Identified Service activities in the Zonal Master Plan of the concerned regulated Areas in the State.
- (v) Land notified and designated for the identified activities in regulated areas, the building map has been approved by the competent authority of the concerned development authority for setting up the project.
- (vi) The land has been declared as non-agriculture land under section-143 of the Uttar Pradesh (Uttarakhand) Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 as amended from time to time, by the competent authority for such purpose;
- (g) "Industrial/Service Sector" Unit means any such industrial unit/project or eligible service sector enterprise which is a registered enterprise under the Goods and Services Tax Act, 2017 and for which acknowledgment has been obtained by filing IEM Part-A (Letter of Intent) in the Government of India, Department of Industry Promotion and Internal Trade (Secretariat of Industrial Assistance);
- (h) "Implementing Agency" means the Industrial Development Department of the Government of Uttarakhand or the office of the Director General and Commissioner of Industries, Uttarakhand, which has been designated as the implementing agency for the implementation of the policy ;
- (i) "Large project" or "Large unit" means a new or substantial expansion unit by which fixed capital investment of Rs 50 crore to Rs 75 crore has been made in land, building and plant and machinery or equipment ;
- (j) "Mega project" or "Mega unit" means a new or substantial expansion unit by which fixed capital investment of Rs 75 crore to Rs 200 crore has been made in land, building and plant and machinery or equipment ;
- (k) "Manufacturing Enterprise" means an industrial undertaking or any other establishment, by whatever name called, engaged in the manufacture or production of goods in any manner whatsoever; which relates to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation Act, 1951) (55 of 1951) and which is defined as a manufacturing enterprise in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 ;

- (l) "New industrial unit" means the industrial unit which has been obtained In-principle Approval under Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012 for setting up a Large, Mega, Ultra Mega and Super Ultra Mega Projects with the approval of State / District Empowered Committee by submitting Common Application Form-1 on www.investuttarakhand.com Portal ;
- (m) "New project/unit" means the project/unit which has established and started their commercial production during the validity period of Mega Industrial and Investment Policy-2021 (MIIP-2021) ;
- (n) "Nodal agency" means, the State Udyog Mitra Cell or Single Window System Cell in Directorate of Industries, Uttarakhand which has been authorized to receive the applications, forward/submit them for scrutiny/testing and acceptance of the applications at the appropriate level under this policy. The Directorate of Industries or such other officer authorized by it shall act as the authorized officer of the nodal agency ;
- (o) "Policy" means the Mega Industrial and Investment Policy, 2021;
- (p) "Scrutiny Committee" means the committee constituted to scrutinize the applications and claims received under the guidelines and policy as mentioned in Annexure-A to these guidelines ;
- (q) "Service Enterprise" means an enterprise engaged in providing or rendering of services as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and such activity is included in the eligible service activities under this policy ;
- (r) "Stamp surcharge means" a surcharge defined as the stamp surcharge payable under the Indian Stamp Act, 1899 (as in force in the State of Uttarakhand) ;
- (s) "State Goods and Services Tax (CGST)" means the State Goods and Services Tax levied under section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 6 of the year, 2017) ;
- (t) State Level Committee shall mean the relevant rules as amended from time to time read with sub-section (1) of section 3 of the Uttarakhand Enterprise Single Window Clearance and Facilitation Act, 2012 (hereinafter referred to as the Single Window Act) or any other committee as may be prescribed from time to time for sanction of benefits under the policy is from the State Level Committee as prescribed.
- (u) "Substantial Expansion" means the minimum fixed capital investment limit prescribed for large, mega, ultra mega and super ultra mega projects in the land, building and plant and machinery/equipment of the existing industrial unit/project for

the purpose of capacity expansion/modernization and innovation, namely Rs. 50 crore, Rs. 75 crore, Rs. 200 crore and Rs. 400 crore or more accretion of Fixed capital investment;

(v) Super Ultra Mega Project or Super Ultra Mega Project Unit means a new or substantial expansion unit by which fixed capital investment of more than Rupees 400 crores has been made in land, building and plant and machinery or equipment ;

(w) Ultra mega project or Ultra Mega unit means a new or substantial expansion unit by which fixed capital investment of Rs 200 crore to Rs 400 crore has been made in land, building and plant and machinery or equipment ;

3. Eligibility Criteria

(a) The identified new industrial units / activities or existing units / activities which are going under expansion in the designated / defined Area / Estate / Land in Para-2(j) of this guidelines, will be covered in this Policy.

(b) Only those new industrial unit/project/service enterprise or existing unit identified under the policy, which is investing capital of more than fifty crore rupees for the establishment/expansion of the unit, will be covered under this policy and will be eligible to avail the benefits of financial incentives and concessions provided in the Mega Industrial and Investment Policy, 2021.

(c) For calculating this amount in case of new project/unit apart from fixed capital asset the value of land and Land development cost (as actually paid / required to be paid) may be added subject to a maximum ceiling of 10 Acre of land for every Rs. 50 Crore Capital Investment.

(d) In case of expansion of existing unit, only the additional capital investment (land, building and plant and machinery) will be taken into account for computing. All benefits, incentives, concessions under this policy for the expanded portion of the existing unit shall be applicable at each stage of expansion of the existing unit. The benefits, incentives and concessions shall be considered from the date of first commercial production of the respective extended phase/s during the validity period of this policy.

(e) Calculation of capital investment will include fixed investment in land, building, new plant and machinery, equipment, components, moulds, dies, jigs and actual assets (Except consumable, disposable or revenue chargeable items) unit which is basically required for the operation of the unit.

(f) Plant & Machinery means newly purchased industrial plant & machinery installed at site and does not include displaced / recycled / refurbished plant & machinery from elsewhere.

4. **Eligibility Certificate**

- (g) Such units which are already receiving grants/incentives from any department / agency under the State / Central Government / foreign agency, will not be eligible for incentive of similar nature under this policy.
- (a) Eligibility Certificate is a certificate which shall be issued by the competent authority in this regard. This shall be issued ensuring that all criteria for eligibility have been fulfilled to the full satisfaction of the competent authority.
- (b) The industrial unit/enterprise identified under the policy shall apply online on the prescribed format along with the required documents/records to the authorized officer of the designated nodal agency for eligibility certificate within 90 days from the date of commencement of commercial production.
- (c) After applying on the prescribed format of online application form to the concerned authority for eligibility certificate, three copies of the printed application form will be submitted with requisite records countersigned to the nodal agency.
- (d) The nodal agency or its authorized representative will initially check the application form that the application form has been filled properly and whether requisite records etc. have been attached with the application and shall enter the same in the register maintained for this purpose. After that the application form will be forwarded to the disbursing agency SIIDCUL for checking/examination of the application. The disbursing agency SIIDCUL will primarily scrutinize the application & its records and after examination the application will be submit for final recommendation before the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.
- (e) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for being placed before the State Level Committee.
- (f) The Nodal Agency will place the application before the State Level Committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee. After getting approval on the application of eligibility certificate from the State Level Committee, the authorized officer of the nodal agency will issue the eligibility certificate in the prescribed format within a week.
- (g) In case of expansion of existing units, date of commencement of production before expansion, details of capital investment, employment and product produced or service rendered (including production capacity), capital investment after expansion, employment generation, proposed product/service (including production capacity) enterprise registration or IEM Part-A & Part-B shall also be submitted along with the application form.

- (h) In case of existing unit under expansion, eligibility certificate will be submitted along with the application format, duly certified by the Chartered Engineer/Chartered Accountant for the assessment of plant and machinery/equipment and building and the certificate of capital investment. The capital investment of the unit for the extended purpose shall be calculated on the basis of capital investment made after expansion till the date of commercial production of the proposed product/operation of the service rendered.
- (i) The State Level Committee may allow the delay in submission of application for eligibility certificate to be condoned on the basis of merit.
- (j) Unless the State Level Committee approves any claim, any right for any incentive under the policy or recommends acceptance of the claim, the unit shall not be deemed to have satisfied the conditions of the policy.
- (k) No claim can be made for any incentive under the policy without the eligibility certificate issued under the policy by the concerned implementing agency and the unit will have to comply with the actual conditions of the eligibility certificate to the satisfaction of the competent authority.
- (l) The decisions of the implementing agency shall be final and binding subject to such directions as may be issued by the Government from time to time in this regard.
- (m) A unit after obtaining the eligibility certificate shall be eligible to apply for all kinds of concessions, incentives, subsidies, reimbursements under this policy.

5. Provisional Eligibility Certificate (PEC)

- (a) Provisional eligibility Certificate is such a certificate which has been issued by the Competent Authority in this regard before undertaking commercial production/service operation for establishment of new unit or expansion of existing unit, exemption/concession of land rates from SIIDCUL and to claim reimbursement of stamp duty chargeable in respect of land leased or purchased.
- (b) To obtain provisional eligibility certificate under Mega Industrial and Investment Policy-2021, the concerned unit can apply online on the prescribed format with requisite records and certificates to the nodal agency after getting in-principle approval for establishment of new project/expansion of existing project under Single Window System.
- (c) After the online submission of the application form for provisional eligibility certificate, three copies of the printed / paper copy of the application form along with the requisite records will be submitted to the competent authority of the concerned nodal agency within 15 days.

- (d) The nodal agency or its authorized representative will initially check the application form that the application form has been filled properly and whether the relevant records etc. have been attached with the application or not and the same shall be entered in the register maintained for this purpose. The Nodal Agency will forward the application form to SIIDCUL for scrutiny by the Scrutiny Committee expeditiously. Incomplete / ineligible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.
- (e) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for being placed before the State Level Committee.
- (f) The Nodal Agency will place the application before the State Level Committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee. After approval of the application for eligibility certificate from the State Level Committee, the authorized officer of the nodal agency will issue the provisional eligibility certificate in the prescribed format within a week.
- (g) After obtaining the provisional eligibility certificate, a unit under the policy will be eligible to apply for concession/rebate in land price and reimbursement of stamp duty charges from SIIDCUL.
- (h) For establishment of new unit or expansion of existing unit, acknowledgment of IEM Part-A can be obtained from Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India and Department of Industry Promotion and Internal Trade (Secretariat of Industrial Assistance), Government of India or In-principle approval from competent authority under Single Window System.

6. Eligible / Non-eligible items of civil works and plant & machinery

- a. **Eligible Civil Works:** The following civil works directly connected with manufacturing process/providing services shall be considered eligible for consideration as eligible civil works:-
 - (i) Factory shed/building with utility areas directly involved in manufacturing and necessary ancillary processes i.e. Plant Stores, Quality Control, Power Room, Maintenance Workshop (actual or rates approved by Public Works Department, whichever is lower).
 - (ii) Required residential facilities as per the effective SIDA standard as applicable.
 - (iii) Construction of raw material and finished product warehouse in the factory premises (Actual or effective rates notified by Public Works Department, whichever is lower).
 - (iv) Necessary civil construction works like machines, equipment (actual or effective rates of PWD schedule, whichever is less).
 - (v) Engineer certificate will be submitted in the prescribed format.

- (vi) The actual cost of civil works shall be submitted in the prescribed format.
- b. **Non-eligible civil works:** The following civil works directly connected with manufacturing process/providing services shall be considered as ineligible for consideration as Non-eligible civil works (list is not exhaustive)-
 - (i) Boundary Wall & Gate.
 - (ii) Approach Road / Internal Road.
 - (iii) Office Building / Space utilized for office.
 - (iv) Raw material / finished product godown situated at a different location other than factory premises.
 - (v) Any residential building or rest house / guest house.
 - (vi) Cafeteria.
 - (vii) Labour rest room and quarters for workers.
 - (viii) Security / Guard room or enclosures.
 - (ix) Construction bridge load.
 - (x) Consultancy fee, taxes etc.
- c. **Eligible Plant & Machinery:**
 - (i) Original price of machinery / equipment directly connected to manufacturing process.
 - (ii) Accessories like tools, jigs, dies, moulds directly connected to manufacturing process.
 - (iii) Motors connected with Plant & Machinery.
 - (iv) Machinery/equipment installation, erection and commissioning.
 - (v) Transportation charges, Transit Insurance, VAT / CST, Excise Duty, Entry Tax etc. paid (in case of indigenous machinery / equipment).
 - (vi) Import duty, shipping charges, CVD, container handling charges, customs clearance charges, VAT / CST, transportation charges from port, entry tax etc. paid (in the case of imported machinery / equipment).
 - (vii) Quality Control (R&D), Pollution Control and Fire Fighting Equipment.
 - (viii) Electrical installations including internal electrification. Panel Board, dedicated transformer, gas producer plant, power generating set etc.
 - (ix) Payment against all the above items must be made by A/c payee cheque/ Demand Draft / NEFT / RTGS which should be reflected in the Bank Statement to be submitted with the application for Eligibility Certificate.

- (x) Elevation and installation related charges paid on actual basis in the manufacturing sector
- (xi) Chartered Accountant Certificate (CA Certificate) shall be submitted in the prescribed format.

d. Non-Eligible Plant & Machinery:

- (i) Plant & Machinery not directly related to manufacturing process.
- (ii) Fuel, Consumables, Spares and Stores.
- (iii) Computers and Office Furniture.
- (iv) Vehicles.
- (v) Second hand / Old Machinery.
- (vi) Closed circuit CCV Camera and Security System related equipment.
- (vii) Stationery items.

7. Others

- (a) **Scheduling of Capital Investment:** In case of any variation arising in the determination of capital investment, the State Level Committee/Approving Authority shall examine and decide the same.
- (b) In case of existing unit under expansion, eligibility certificate will be submitted along with the application format, duly certified by the Chartered Engineer/Chartered Accountant for the assessment of plant & machinery/equipment and building and the certificate of capital investment. The capital investment of the unit for the extended purpose shall be calculated on the basis of capital investment made after expansion till the date of commercial production of the proposed product/operation of the service rendered.
- (c) New units availing benefits/concessions/incentives under the policy and existing units undertaking expansion shall be eligible to apply for the concessions/financial incentives provided in the policy after six months of commencement of commercial production/operation of the service.
- (d) The last date for investment in civil construction as well as plant and machinery shall be from the date of receipt of in-principle approval under single window arrangement to the date of commencement of commercial production/service operation as recorded in Udyam Registration/IEM-Part-B.
- (d) The disbursing agency shall ensure that funds are released against incentives, concessions, benefits, reimbursements by the State Level Committee subject to availability and allocation of funds sanctioned by the Government.

- (f) State Level Committee on the basis of the recommendation of the Scrutiny Committee on its claim/revised claim of an application or to approve on certain other valid grounds or to reject it or an application/claims may be kept pending for the purpose of non-availability of sufficient funds for the purpose as it deems fit.
- (g) If it is confirmed that an industrial unit has fraudulently attempted to obtain the financial incentives provided for in this policy by giving false information or if the unit ceases production within 5 years of commercial production/service operation, then After giving that unit an opportunity of being heard, such unit may be asked to return the grant or the financial assistance provided. This grant/reimbursement assistance will be released through digital payment and SIIDCUL can take an affidavit in this regard from the beneficiary industrial units. A contract will also be executed between the industrial unit and the disbursing agency SIIDCUL before distribution to the beneficiary unit fulfilling all the requirements of the scheme.
- (h) The concerned authority may ask the unit to refund the error availed of the benefits within a period of 30 days. If the unit fails to do so, the authority may take legal action in a court of competent law for recovery of the amount along with interest thereon and such penal action as permissible under the law.
- (i) If any unit fails to undertake commercial production within a period of three years from the date of allotment of land or Provisional eligibility certificate or issue of eligibility certificate, whichever is earlier, the benefits given under the policy can be withdrawn. From the date of commencement of commercial production, if any unit closes after three consecutive years of production, then the amount of grant/subsidy so approved by the concerned committee will be released to the concerned unit through their bank or financial institutions.
- (j) All eligible units shall submit an undertaking as per the prescribed format giving details that the information furnished along with the application form is correct.

8. Right to Modify /Amend etc.

- (a) The State Government shall have the right at any time to extend, modify or repeal any part of the Guidelines in the public interest.
- (b) The State Government may, in appropriate cases, after careful consideration of profit and loss, make concessions in respect of the application or non-applicability of any particular provision of this policy.
- (c) The State Government may, after careful consideration of appropriate matters, modify any incentive/benefit under the policy or extend any condition or impose additional conditions, if it so desires.

9. **Miscellaneous** (a) If any clarification is required regarding the implementation of these guidelines, the Department of Industrial Development, Government of Uttarakhand will be authorized to issue necessary clarifications in this regard.
- (b) If there is any ambiguity in any matter, Industrial Development Department, Government of Uttarakhand will have the jurisdiction to interpret any of the provisions correctly.
10. **Rectification of Mistake** With a view to rectifying any error noticed on the records in the composition of the amount of grant under the policy. The Competent Authority may, by its order, distribute the grant to such unit and recover the excess payment, if any, at the rate of 12 percent per annum. No such order shall be issued for the benefits given under this scheme after a period of one year from the end of the financial year where the benefits have been fully availed.
11. **Appeal** (a) The State Level Committee shall have the power to hear and dispose of any appeal against the orders of the Competent Authority of the concerned Department/Implementing Agency/Disbursing Agency.
- (b) An appeal can be made to the State Government against any order/decision of the State Level Committee.
- (c) Application for appeal may be made within a period of 30 days from the date of communication of the decision.
12. **Authority to issue Clarification / Modification / Refinement** (a) The Uttarakhand government will have the right to amend/modify/clarify the policy as and when it is necessary in the public interest. However, as and when necessary, keeping in view the convenience in implementation of the draft policy attached to this policy, can be modified, changed, expanded or repealed by the Department of Industrial Development.
- (b) If there is any ambiguity in any matter, Industrial Development Department, Government of Uttarakhand will have the jurisdiction to interpret any of the provisions correctly.
- (c) The State Government may, in appropriate cases, after careful consideration of profit and loss, make concessions in respect of the application or non-applicability of any particular provision of this policy.
- (d) Department of Industrial Development, Government of Uttarakhand shall have the authority to issue necessary clarification in case any clarification is sought regarding implementation of these guidelines / rules.
- (e) Department of Industrial Development shall have the right to correctly interpret any provision of these guidelines in case of any ambiguity.

Chapter-Two

Benefits/Concessions/Incentives to Eligible Units

- 13. Allotment of land through SIIDCUL**
- The allotment of land to the willing applicants under these provisions will be done by SIIDCUL under single window system as per the guidelines as decided from time to time and effective rates of SIIDCUL.
 - Based on the provisional eligibility certificate issued by the Competent Authority under this policy in allotment of land, a special discount/concession of 15 percent for large projects, 25 percent for mega projects and 30 percent for ultra mega & super ultra mega projects will be given at the effective rates of SIIDCUL.
 - Under this policy, 20% of the value of land allotted by SIIDCUL (after rebate) will be paid at the time of allotment of land and balance amount will be payable in equal installments of 5 years along with fixed interest.
- 14. Incentives and other concessions under the policy for eligible Large/Mega/Ultra Mega/Super Ultra Mega Projects**
- Reimbursement of Seven percent interest assistance will be provided to eligible units on term loans for the next five years from the date of commencement of commercial production, with a maximum annual limit of Rs 25 lakh, Rs 35 Lakhs, Rupees 50 Lakhs and Rupees 75 Lakhs for Large, Mega, Ultra Mega And Super Ultra Mega projects respectively..
 - The maximum limit and quantum of reimbursement of net SGST payable after adjustment of Input Tax Credit (ITC) on B2C sale of finished goods shall be as under:-
 - 30% of the total net SGST tax liability after adjustment of Input Tax Credit for the next 5 years from the date of production for Large Projects, sold to customers (B to C) within the state.
 - 50% of the total net SGST tax liability after adjustment of Input Tax Credit for the next 5 years from the date of production for Mega Projects / Ultra Mega Projects / Super Ultra Mega Projects, sold to customers (B to C) within the state.

Explanation:

- Whatever tax liability is created under the Goods and Services Tax Act, the entire amount related to it will be deposited in the treasury and no part will be kept with itself. Reimbursement of part of such SGST tax paid under Goods and Services Tax (GST) paid to the entity in accordance with the provisions of this scheme in view of the total tax liability after adjustment of ITC as per the return filed and Which is related to the sale directly to the customer (B2C) within the state.
- The benefit of SGST reimbursement assistance will be admissible to manufacturing industries only.

- iii. Reimbursement assistance will be admissible to the eligible enterprises at the rate of Rs.1.00 per unit in the electricity bill payable for the next 5 years from the date of commencement of production. The maximum annual limit of electricity reimbursement assistance will be Rs 50 lakh per annum for large projects, Rs 75 lakh per year for mega projects, Rs 1 crore per year for ultra mega projects and Rs 1.50 crore per year for super ultra mega projects.

Explanation: The benefit of reimbursement assistance payable in electricity bill to hotels, resorts, ropeways, motels, hospitals etc. included in the eligible service activities identified under the policy will not be admissible.

- iv. The eligible enterprises will be reimbursed 100% of the electric duty due/paid on the electricity bill consumed in the production work for the next 5 years from the date of commencement of production to the eligible enterprises.

Explanation: The benefit of reimbursement assistance will not be admissible on electric duty paid to hotels, resorts, ropeways, motels, hospitals, etc. included in the eligible service activities identified under the policy.

- v. Reimbursement assistance of 50 percent will be given on the stamp duty charges payable in the execution of land purchase deed and lease deed.
- vi. Reimbursement of registration fee payable / paid for execution of Land purchase / lease deed @ of Rs. 999 per Rs. 1000 shall be given.
- vii. Capital subsidy up to 30%, subject to a maximum of Rs. 50 lakh, will be payable on the establishment of an ETP plant.
- viii. **Payroll Assistance to encourage massive employment generation:** There shall be a minimum specified limit of regular employment of 50 people for large projects, 100 for mega projects, 200 for ultra mega projects and 400 for super ultra mega projects for allowing payroll assistance. Enterprises where regular employees are employed in excess of the specified limit, shall be given pay-roll assistance as gratuity at the rate of Rs.500/- per employee per month for the next 5 years on the employees employed in addition to the specified limit. For women employees, this rate shall be Rs 700/- per employee per month.

Chapter-Three

Provisions, Procedures and Disbursement of Benefits

15. Reimbursement of Interest Subsidy:**(a) Provision for reimbursement of interest assistance.**

- (i) Units receiving any similar benefits or incentives or subsidies under any other scheme/benefits of the Central Government or State Government shall not be eligible to receive benefits under this scheme.
- (ii) Reimbursement of Interest Subsidy will be admissible on term loans taken from nationalized banks / scheduled commercial banks and other financial institutions recognized by the Reserve Bank of India for financing. Any term loan taken before the commencement of the policy, the first installment of which has been disbursed before the commencement of this policy, the benefit of reimbursement of interest subsidy will not be admissible.
- (iii) Reimbursement of Interest Subsidy will be admissible for a period of five years or till the period of repayment of loan, whichever is earlier. The period of reimbursement of interest subsidy will be taken into account from the date of disbursement of the first installment to the permissible period.
- (iv) Reimbursement of Interest Subsidy will be given to such units which have regularly paid installment and interest to financial institutions/banks. If the units fail in this, the reimbursement of interest subsidy for the failure period will not be given and such failure period will be deducted from the period of five years as mentioned in above Sub Clause (iii) of above.

(b) Procedure for claiming Reimbursement of Interest Subsidy:

- (i) The eligible units desirous of availing the reimbursement of interest subsidy under the policy will have to submit the claim of reimbursement of interest subsidy on the prescribed format on the www.investuttarakhand.com portal under single window system along with the requisite documents. Along with the application for reimbursement of interest subsidy, a certificate from the concerned bank/financial institution to the effect that the unit is repaying the principal and interest regularly, will have to be submitted. Banks will also mention in the certificate any failure to repay the principal/interest. The first application for the claim of reimbursement of interest subsidy will be made within 45 days after the commencement of commercial production. Thereafter claims will be submitted on quarterly basis within 45 days after the end of the quarter.
- (ii) The application form will be submitted to the concerned nodal officer in the prescribed format on the www.investuttarakhand.com portal. In case of online submission, three sets of print of the application form along with all the attached documents will also be submitted to the nodal agency after due signature. The nodal agency or its authorized representative shall initially check the application form whether the application form has been properly filled and whether the relevant records etc. have been attached with the application and shall enter the same in the register maintained for the purpose. Thereafter, the application form will be forwarded to the General Manager, SIIDCUL to be presented before the Scrutiny Committee at the earliest. After scrutinizing / examining the applications received from the level of SIIDCUL, they will be presented for the scrutiny of the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.
- (iii) Where the application is submitted after the time period as provided above in sub-clause (i), the maximum delay of 90 days in the submission of the application from the prescribed date of application may be allowed on the approval of the State Empowered Committee.
- (iv) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for placing it before the State Level Committee. The Nodal Agency will place the application before the State Level Committee in the next

meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee.

- (v) The State Empowered Committee will take a decision after considering the applications recommended by the Scrutiny Committee. Information about the decision taken by the State Empowered Committee by the nodal agency, which will contain the details of the date of the meeting, the sanctioned amount, the minutes. Immediately after the decision taken in the meeting, which shall not exceed seven days from the date of the meeting, shall be forwarded to all the parties concerned and to the disbursing agency.
- (vi) Where the State Level Committee is of the opinion that the unit is not eligible for reimbursement of interest subsidy, it shall give such unit an opportunity of being heard and shall record the reasons for the refusal in writing. The decision of the committee will be communicated to the unit and all concerned by the nodal agency of the state empowered committee immediately after but within a maximum of seven days from the date of the decision taken by the state level committee meeting.

(c) Procedure for disbursement of Reimbursement of Interest Subsidy:

- (i) Reimbursement of Interest Subsidy will be disbursed only after the commencement of commercial production.
- (ii) The designated disbursing agency or any officer authorized by the disbursing agency, on receipt of intimation from the Member Secretary, State Level Committee, shall pass an order for reimbursement of the approved claim amount subject to the availability of funds for the purpose and the approved amount will be transferred immediately to the concerned unit through Demand Draft/Pay Order/Cheque/RTGS directly into the bank account.

16. Electricity Subsidy / Electricity Bill Subsidy

(a) Provision for Electricity Assistance:

- (i) Eligible units will be given this assistance for the next five years after the date of commencement of commercial production.
- (ii) Large, Mega, Ultra Mega And Super Ultra Mega Projects will be given reimbursement assistance at the rate of Rupee 1 per unit for the next five years after commencement of commercial production, on the bills of electricity consumed in the production work up to the maximum specified limit. The maximum annual limit of electricity reimbursement assistance will be Rs 50 lakh per annum for large projects, Rs 75 lakh per year for mega projects, Rs 1 crore per year for ultra mega projects and Rs 1.50 crore per year for super ultra mega projects.
- (iii) 100% reimbursement of electricity surcharge to eligible manufacturing units for the next five years after the date of commencement of commercial production.
- (iv) Reimbursement of one rupee per electricity surcharge paid and power unit consumed shall be applicable only on single connections given to units for industrial use for manufacturing/generation or for related purposes only.

(b) Procedure for claiming Electricity Assistance:

- (i) Eligible units will apply online on the prescribed format to the nodal agency for electricity reimbursement assistance and reimbursement of electricity surcharge. The eligible unit shall submit its first claim within 45 days after the commencement of commercial production. Thereafter on quarterly basis the claims will be submitted within 45 days after the end of the quarter.
- (ii) The application form will be submitted to the concerned nodal officer in the prescribed format on www.investuttarakhand.com portal. In case of online submission, three sets of print of the application form along with all the attached documents will also be submitted to the nodal agency after due signature. The nodal agency or its authorized representative shall

initially check the application form whether the application form has been properly filled and whether the relevant records etc. have been attached with the application and shall enter the same in the register maintained for the purpose. Thereafter, the application form will be forwarded to the General Manager, SIIDCUL to be presented before the Scrutiny Committee at the earliest. After scrutinizing / examining the applications received from the level of SIIDCUL, they will be presented for the scrutiny of the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.

- (iii) Where the application is submitted after the time period as provided above in sub-clause (i), the maximum delay of 90 days in the submission of the application from the prescribed date of application may be allowed on the approval of the State empowered committee.
- (iv) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for placing it before the State Level Committee. The Nodal Agency will place the application before the State Level Committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee.
- (v) The State empowered committee will take a decision after considering the applications recommended by the Scrutiny Committee. Information about the decision taken by the State empowered committee by the nodal agency, which will contain the details of the date of the meeting, the sanctioned amount, the minutes. Immediately after the decision taken in the meeting, which shall not exceed seven days from the date of the meeting, shall be forwarded to all the parties concerned and to the disbursing agency.
- (vi) Where the State Level Committee is of the opinion that the unit is not eligible for Electricity Assistance/ Electricity Bill Subsidy, it shall provide such unit an opportunity of being heard and record the reasons for refusal in writing. The decision of the committee will be communicated to the unit and all concerned by the nodal agency of the state empowered committee immediately after but within a maximum of seven days from the date of the decision taken by the state level committee meeting.

(c) **Procedure for Distribution of Electricity Assistance:**

The designated disbursing agency or any officer authorized by the disbursing agency shall, on receipt of intimation from the nodal agency, pass an order for reimbursement of the approved claim amount, subject to availability of funds for the purpose and will transfer it directly to the bank account through Demand Draft/Pay Order/Cheque/RTGS to the concerned unit expeditiously.

17. Stamp Surcharge:

(a) **Provision for exemption/reimbursement of stamp surcharge:**

Eligible units will be reimbursed 50% of the payment of stamp surcharge on land purchase/execution of land lease.

(b) **Procedure for Exemption of Stamp Surcharge:**

- (i) The units eligible for expansion of the existing unit or for setting up a new unit under this policy shall submit the duly filled application form in the prescribed format to the Nodal Agency in the format "Application for Claim for Reimbursement of Stamp Surcharge". Within 45 days after the execution of the deed, the claim of reimbursement assistance will be submitted along with the provisional eligibility certificate and an affidavit will have to be attached in support of the facts mentioned in the application form.
- (ii) The application form will be submitted to the concerned nodal officer in the prescribed format on www.investuttarakhand.com portal. In case of online submission, three sets of print of the application form along with all the attached documents will also be submitted to the nodal agency after due signature. The nodal agency or its authorized representative shall initially check the application form whether the application form has been properly filled

and whether the relevant records etc. have been attached with the application and shall enter the same in the register maintained for the purpose. Thereafter, the application form will be forwarded to the General Manager, SIIDCUL to be presented before the Scrutiny Committee at the earliest. After scrutinizing / examining the applications received from the level of SIIDCUL, they will be presented for the scrutiny of the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.

- (iii) Where the application is submitted after the time period as provided above in sub-clause (i), the maximum delay of 90 days in the submission of the application from the prescribed date of application may be allowed on the approval of the State empowered committee.
- (iv) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for placing it before the State Level Committee. The Nodal Agency will place the application before the State Level Committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee.
- (v) The State empowered committee will take a decision after considering the applications recommended by the Scrutiny Committee. Information about the decision taken by the State empowered committee by the nodal agency, which will contain the details of the date of the meeting, the sanctioned amount, the minutes. Immediately after the decision taken in the meeting, which shall not exceed seven days from the date of the meeting, shall be forwarded to all the parties concerned and to the disbursing agency.
- (vi) Where the State Level Committee is of the opinion that the unit is not eligible for exemption/reimbursement of stamp surcharge, it shall provide such unit an opportunity of being heard and record the reasons for refusal in writing. The decision of the committee will be communicated to the unit and all concerned by the nodal agency of the state empowered committee immediately after but within a maximum of seven days from the date of the decision taken by the state level committee meeting.

(c) Procedure for reimbursement of stamp surcharge paid:

The designated disbursing agency or any officer authorized by the disbursing agency shall, on receipt of intimation from the nodal agency, pass an order for reimbursement of the approved claim amount, subject to availability of funds for the purpose and will transfer it directly to the bank account through Demand Draft/Pay Order/Cheque/RTGS to the concerned unit expeditiously.

18. Reimbursement of Registration Fee:

(a) Provision for reimbursement of registration fee:

Under this policy, the eligible unit will be given a reimbursement assistance of Rs.999 on registration fee of Rs.1000 in respect of fee paid for registration of purchase deed/lease deed.

(b) Procedure for claiming reimbursement of registration fee:

- (i) Eligible unit desirous of availing reimbursement of registration fee paid, shall submit a duly completed application form "Application for reimbursement of registration Fee" in prescribed format along with details of registration fee paid along with proof of payment duly certified by Chartered Accountant and an affidavit in support of the facts of the application, to the Nodal Agency within 45 days of registration of land purchase/lease deed.
- (ii) The application form will be submitted to the concerned nodal officer in the prescribed format on www.investuttarakhand.com portal. In case of online submission, three sets of print of the application form along with all the attached documents will also be submitted to the nodal agency after due signature. The nodal agency or its authorized representative shall initially check the application form whether the application form has been properly filled and whether the relevant records etc. have been attached with the application and shall enter

the same in the register maintained for the purpose. Thereafter, the application form will be forwarded to the General Manager, SIIDCUL to be presented before the Scrutiny Committee at the earliest. After scrutinizing / examining the applications received from the level of SIIDCUL, they will be presented for the scrutiny of the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.

- (iii) Where the application is submitted after the time period as provided above in sub clause (i) the maximum delay of 90 days in the submission of the application from the prescribed date of application may be allowed on the approval of the State empowered committee.
- (iv) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for placing it before the State Level Committee. The Nodal Agency will place the application before the State Level Committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee.
- (v) The State empowered committee will take a decision after considering the applications recommended by the Scrutiny Committee. Information about the decision taken by the State empowered committee by the nodal agency, which will contain the details of the date of the meeting, the sanctioned amount, the minutes. Immediately after the decision taken in the meeting, which shall not exceed seven days from the date of the meeting, shall be forwarded to all the parties concerned and to the disbursing agency.
- (vi) Where the State Level Committee is of the opinion that the unit is not eligible for reimbursement of registration fee, it shall provide such unit an opportunity of being heard and record the reasons for the refusal in writing. The decision of the committee will be communicated to the unit and all concerned by the nodal agency of the state empowered committee immediately after but within a maximum of seven days from the date of the decision taken by the state level committee meeting.

(c) Procedure for Disbursement:

The designated disbursing agency or any officer authorized by the disbursing agency shall, on receipt of intimation from the nodal agency, pass an order for reimbursement of the approved claim amount, subject to availability of funds for the purpose and will transfer it directly to the bank account through Demand Draft/Pay Order/Cheque/RTGS to the concerned unit expeditiously.

19. Capital subsidy on ETP:

(a) Provision for subsidy for setting up of ETP plant:

- (i) Under the policy, eligible projects/units will be given capital subsidy assistance of 30 percent on the installation cost of the ETP plant, subject to a maximum of Rs.50 lakh.
- (ii) A unit receiving similar subsidy under any other scheme/package of the Central/State Government shall not be eligible for capital subsidy under this policy.
- (iii) Subsidy for setting up of ETP will be calculated on fixed capital investment directly linked to the establishment of ETP.
- (iv) Eligible units can submit subsidy claim for installation of ETP after successful completion of ETP plant.

(b) Procedure for Submission of Gratuity Claim on Establishment of ETP:

- (i) Eligible unit desirous of availing subsidy on establishment of ETP, shall submit a duly completed application form "Application for claim of Subsidy for ETP" in prescribed format along with details of Bill vouchers along with proof of payment duly certified by Chartered Accountant and an affidavit in support of the facts of the application, to the Nodal Agency within 45 days of successful completion of ETP unit.

- (ii) The application form will be submitted to the concerned nodal officer in the prescribed format on www.investuttarakhand.com portal. In case of online submission, three sets of print of the application form along with all the attached documents will also be submitted to the nodal agency after due signature. The nodal agency or its authorized representative shall initially check the application form whether the application form has been properly filled and whether the relevant records etc. have been attached with the application and shall enter the same in the register maintained for the purpose. Thereafter, the application form will be forwarded to the General Manager, SIIDCUL to be presented before the Scrutiny Committee at the earliest. After scrutinizing / examining the applications received from the level of SIIDCUL, they will be presented for the scrutiny of the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.
- (iii) Where the application is submitted after the time period as provided above in sub-clause (i), a maximum delay of 90 days in submission of the application from the prescribed date of application may be considered with the approval of the State empowered committee.
- (iv) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for placing it before the State Level Committee. The Nodal Agency will place the application before the State empowered committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee.
- (v) The State empowered committee will take a decision after considering the applications recommended by the Scrutiny Committee. Information about the decision taken by the State empowered committee by the nodal agency, which will contain the details of the date of the meeting, the sanctioned amount, the minutes. Immediately after the decision taken in the meeting, which shall not exceed seven days from the date of the meeting, shall be forwarded to all the parties concerned and to the disbursing agency.
- (vi) Where the State Level Committee is of the opinion that the unit is not eligible for subsidies for setting up of ETP, it shall provide such unit an opportunity of being heard and record the reasons for refusal in writing. The decision of the committee will be communicated by the nodal agency of the state empowered committee to the unit and all concerned immediately after but within a maximum of seven days from the date of the decision taken by the state level committee meeting.

(c) Procedure for Disbursement:

The designated disbursing agency or any officer authorized by the disbursing agency shall, on receipt of intimation from the nodal agency, pass an order for reimbursement of the approved claim amount, subject to availability of funds for the purpose and will transfer it directly to the bank account through Demand Draft/Pay Order/Cheque/RTGS to the concerned unit expeditiously.

20. Payroll Assistance to encourage massive employment generation:

(a) Provision for Payroll Assistance:

- (i) There will be a minimum specified limit of regular employment of 50 people for large projects, 100 for mega projects, 200 for ultra mega projects and 400 for super ultra mega projects for allowing payroll assistance. Enterprises where regular employees are employed in excess of the specified limit, will be given pay-roll assistance as gratuity at the rate of Rs.500/- per employee per month for the next 5 years on the employees employed in addition to the specified limit. For women employees, this rate will be Rs 700/- per employee per month.
- (ii) Additional employee means the number of employees in excess of the specified number of employees employed.

- (iii) Unit availing similar subsidy under any other scheme/package of Central/State Government will not be eligible for capital subsidy under this policy.

(b) Procedure for Claiming Payroll Assistance:

- (i) Eligible unit desirous of availing reimbursement of payroll assistance shall submit a duly completed application form "Application for claims of payroll assistance" in prescribed format along with details of facts/evidences and details certified by the Labor Department, to the Nodal Agency within 45 days of the employment of more than the specified number of employees.
- (ii) The application form will be submitted to the concerned nodal officer in the prescribed format on www.investuttarakhand.com portal. In case of online submission, three sets of print of the application form along with all the attached documents will also be submitted to the nodal agency after due signature. The nodal agency or its authorized representative shall initially check the application form whether the application form has been properly filled and whether the relevant records etc. have been attached with the application and shall enter the same in the register maintained for the purpose. Thereafter, the application form will be forwarded to the General Manager, SIIDCUL to be presented before the Scrutiny Committee at the earliest. After scrutinizing / examining the applications received from the level of SIIDCUL, they will be presented for the scrutiny of the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.
- (iii) Where the application is submitted after the time period as provided above in clause 6(b)(i) of Chapter-III, the maximum delay of 90 days in the submission of the application from the prescribed date of application may be allowed on the approval of the State empowered committee.
- (iv) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for placing it before the State Level Committee. The Nodal Agency will place the application before the State empowered committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee.
- (v) The State empowered committee will take a decision after considering the applications recommended by the Scrutiny Committee. Information about the decision taken by the State empowered committee by the nodal agency, which will contain the details of the date of the meeting, the sanctioned amount, the minutes. Immediately after the decision taken in the meeting, which shall not exceed seven days from the date of the meeting, shall be forwarded to all the parties concerned and to the disbursing agency.
- (vi) Where the State Level Committee is of the opinion that the unit is not eligible for payroll assistance, it shall provide such unit an opportunity of being heard and record in writing the reasons for the denial. The decision of the committee will be communicated to the unit and all concerned by the nodal agency of the state empowered committee immediately after but within a maximum of seven days from the date of the decision taken by the state level committee meeting.

(c) Procedure for Disbursement:

The designated disbursing agency or any officer authorized by the disbursing agency shall, on receipt of intimation from the nodal agency, pass an order for reimbursement of the approved claim amount, subject to availability of funds for the purpose and will transfer it directly to the bank account through Demand Draft/Pay Order/Cheque/RTGS to the concerned unit expeditiously.

21. Reimbursement of SGST:**(a) Provisions for SGST:**

- (i) The industrial unit/project will get its enterprise registered under the Goods and Services Tax Act, 2017.
- (ii) The maximum limit and quantum of reimbursement of net SGST payable after adjustment of Input Tax Credit (ITC) on B2C sale of self-made goods/items shall be as under:-
 - (A) 30% of the total net SGST tax liability after adjustment of Input Tax Credit for the next 5 years from the date of production for large projects, sold to customers (B to C) within the state.
 - (B) 30% of the total net SGST tax liability after adjustment of Input Tax Credit for the next 5 years from the date of production for Mega Projects / Ultra Mega Projects / Super Ultra Mega Projects, sold to customers (B to C) within the state.

Explanation:

- (i) Whatever tax liability is created under the Goods and Services Tax Act, the entire amount related to it will be deposited in the treasury and no part will be kept with itself. Reimbursement of part of such SGST tax paid under Goods and Services Tax (GST) paid to the entity in accordance with the provisions of this scheme in view of the total tax liability after adjustment of ITC as per the return filed and Which is related to the sale directly to the customer (B2C) within the state.
- (ii) The benefit of SGST reimbursement assistance will be admissible to manufacturing industries only.

(b) Procedure for Reimbursement of SGST:

- (i) According to the provisions of the Goods and Services Tax Act, monthly / quarterly return will be filed by the eligible manufacturing units first and according to the return, whatever tax liability is created under the State Goods and Services Tax (SGST) Act, the entire amount will be deposited in the treasury and no part will be kept with itself. According to the return filed and considering the total tax liability after adjustment of ITC, the unit will be reimbursed the part of such SGST paid under the State Goods and Services Tax (SGST) paid in accordance with the provisions of these guidelines, Which is related to the sale directly to the customer (B to C) within the state.
- (ii) The application form will be submitted to the concerned nodal officer in the prescribed format on www.investuttarakhand.com portal. In case of online submission, three sets of print of the application form along with all the attached documents will also be submitted to the nodal agency after due signature. The nodal agency or its authorized representative shall initially check the application form whether the application form has been properly filled and whether the relevant records etc. have been attached with the application and shall enter the same in the register maintained for the purpose. Thereafter, the application form will be forwarded to the General Manager, SIIDCUL to be presented before the Scrutiny Committee at the earliest. After scrutinizing / examining the applications received from the level of SIIDCUL, they will be presented for the scrutiny of the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.
- (iii) Where the application is submitted after the time period as provided above in sub-clause (i) the maximum delay of 90 days in the submission of the application from the prescribed date of application may be allowed on the approval of the State empowered committee.
- (iv) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for placing it before the State Level Committee. The Nodal Agency will place the application before the State empowered committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the

Scrutiny Committee.

- (v) The State empowered committee will take a decision after considering the applications recommended by the Scrutiny Committee. Information about the decision taken by the State empowered committee by the nodal agency, which will contain the details of the date of the meeting, the sanctioned amount, the minutes. Immediately after the decision taken in the meeting, which shall not exceed seven days from the date of the meeting, shall be forwarded to all the parties concerned and to the disbursing agency.
- (vi) Where the State Level Committee is of the opinion that the unit is not eligible for SGST reimbursement assistance, it shall provide such unit an opportunity of being heard and record the reasons for denial in writing. The decision of the committee will be communicated to the unit and all concerned by the nodal agency of the state empowered committee immediately after but within a maximum of seven days from the date of the decision taken by the state level committee meeting.

(c) Procedure for Disbursement:

The designated disbursing agency or any officer authorized by the disbursing agency shall, on receipt of intimation from the nodal agency, pass an order for reimbursement of the approved claim amount, subject to availability of funds for the purpose and will transfer it directly to the bank account through Demand Draft/Pay Order/Cheque/RTGS to the concerned unit expeditiously.

Chapter-Four

Application Form, Format, Appendix and Enclosure for applying for various Incentives/Benefits/Concessions

The application forms, formats, appendices and attachments for various incentives/benefits/concessions etc. under the policy are as follows. These may be modified or modified by the implementing agency, nodal agency or disbursing agency in such new formats and structures as may be required from time to time:

S.No.	Description	Form Details
1.	Scrutiny Committee	Appendix 1
2.	Application for eligibility certificate (new unit)	EC-1
3.	Application for Certificate of Eligibility (Existing Unit)	EC-1 A
4.	Format of Certificate of Eligibility	EC-2
5.	Application for provisional eligibility certificate	PEC-1
6.	Format of Provisional Eligibility Certificate	PEC-2
7.	Application for Claim of Interest Subsidy	Claim (INT)
8.	Application for Claim of Reimbursement of SGST	Claim (claim)
9.	Application for claim of subsidy/electricity assistance in electricity bill	Claim (PBR)
10.	Application for claim of reimbursement of stamp surcharge	Claim (STD)
11.	Application for claim of reimbursement of registration fee	Claim (RGF)
12.	Application for claiming subsidy of ETP	Claim (ETP)
13.	Application for claim of payroll assistance	Claim (PRA)
14.	Format of Engineer Certificates (for all new units)	Engineer (New Unit)
15.	Format of Engineer Certificates (For Existing Units)	Engineer (Existing Unit)
16.	Statement of Actual Cost of Civil Work	-
17.	Details of investment on plant & equipment and other property	-
18.	Format of Chartered Accountant Certificate (New Entity)	CA-1
19.	Format of Chartered Accountant Certificate (Existing Entity)	CA-2
20.	Form of affidavit	affidavit
21.	Form of undertaking	Enterprise

Appendix A
Scrutiny Committee

S.No.	Members of Committee	Designation
1.	Principal Secretary / Secretary (Industries), Govt. of Uttarakhand.	Chairman
2.	Director General and Commissioner Industries, Uttarakhand or their representatives who are of the level of Director Industries.	Member
3.	Managing Director, SIIDCUL	Member
4.	Additional Secretary, Finance, Government of Uttarakhand.	Member
5.	Director, Finance / Finance Controller, SIIDCUL	Member
6.	General Manager, SIIDCUL	Member Secretary

By Order,

DR. PANKAJ KUMAR PANDEY,

Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 फरवरी, 2023 ई0 (माघ 29, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 18, 2023

No. 21/XIV-a/59/Admin.A/2012--Ms. Payal Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 18 days w.e.f. 06.12.2022 to 23.12.2022.

NOTIFICATION

January 18, 2023

No. 22/XIV-a-15/Admin.A/2009--Shri Bhavdeep Ravtey, Civil Judge (Sr. Div.), Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 18 days w.e.f. 05.12.2022 to 22.12.2022.

NOTIFICATION

January 18, 2023

No. 23/XIV-14/Admin.A/2008--Shri Dharmendra Singh Adhikari, 5th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 29 days w.e.f. 07.11.2022 to 05.12.2022.

NOTIFICATION

January 18, 2023

No. 24/XIV-35/Admin.A/2008--Shri Ramesh Singh, Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 12.12.2022 to 24.12.2022. with permission to prefix 10.12.2022 & 11.12.2022 as second Saturday & Sunday holiday and suffix 25.12.2022 to 31.12.2022 as Christmas holidays & 01.01.2023 as New Year holiday respectively.

NOTIFICATION

January 18, 2023

No. 25/XIV-a-40/Admin.A/2020--Ms. Pratiksha Kesarwani, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 29 days w.e.f. 19.11.2022 to 17.12.2022. with permission to suffix 18.12.2022 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

कार्यालय आदेश

31 दिसम्बर, 2022 ई०

पत्रांक 1264/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)-31/2011-सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्री पान सिंह बिष्ट को, नियमित चयनोपरान्त, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 वेतनमान ₹ 56100-177500 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए एक वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. श्री पान सिंह बिष्ट की पदोन्नति श्री गोपाल सिंह राणा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले एक परिणामी रिक्ति के अधीन दिनांक 01 जनवरी, 2023 अथवा उसके उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री पान सिंह बिष्ट को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

कार्यालय आदेश

31 दिसम्बर, 2022 ई0

पत्रांक 1265/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)-34/2007-सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित प्रशासनिक अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 वेतनमान ₹ 47600-151100 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाता है :-

1. श्री हरेन्द्र सिंह

2. श्री मुकेश कुमार

2. उपरोक्त क्रमांक-1 पर अंकित कार्मिक श्री हरेन्द्र सिंह की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी तथा क्रमांक-2 पद अंकित कार्मिक श्री मुकेश कुमार की पदोन्नति श्री पान सिंह विष्ट वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदोन्नत पद (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी) पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त रिक्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो उपरोक्त कार्मिकों को प्रधान सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

बंशीधर तिवारी,
महानिदेशक।

कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल

कार्यभार प्रमाणक

01 जनवरी, 2023 ई0

संख्या कैम्प/2-प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश File No. PVD 1-IAS/JAG/1/2022-XXX-1 (Computer No. 44239)1/85119/2022 देहरादून, दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, के अनुपालन में कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान रु0 15,600-39,100 + ग्रेड पे रु0 7600/- (पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद का कार्यभार अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 01 जनवरी, 2023 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

अवमोचक अधिकारी,
विनीत तोमर।

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यभार प्रमाण पत्र

06 जनवरी, 2023 ई०

पत्रांक-वाकअधि०/अधिष्ठान/व्य०प०/76(5)/05(10)/2023-प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग-8 द्वारा निर्गत अधिसूचना सं० 86152/2022/07(100)/XXVII(8)/2008, दिनांक 26-12-2022 के क्रम में भाननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की अधिसूचना संख्या 01/UHC/Admin.A/2023 दिनांक 02-1-2023 के अनुक्रम में 'अध्यक्ष, वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून' के पद का कार्यभार का आज दिनांक 06-1-2023 की पूर्वाह्न में निम्नप्रकार हस्तान्तरित किया गया।

अवमुक्त अधिकारी,

सी०पी० बिजलवान,
एच०जे०एस०

अवमोचक अधिकारी,

मलिक मजहर सुल्तान,
एच०जे०एस०
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 फरवरी, 2023 ई० (माघ 29, 1944 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पं०) हरिद्वार

सूचना

09 फरवरी, 2023 ई०

पत्रांक 1890/पं०चु०/2023-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, की अधिसूचना संख्या-1317/रा०नि०आ०/-2/4076/2023 दिनांक 08 फरवरी, 2023 के द्वारा जनपद हरिद्वार की समस्त ग्राम पंचायतों में उप प्रधान ग्राम पंचायत के निर्वाचन निम्न प्रकार समय सारणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं :-

समय सारणी

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटित करने का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
16.02.2023 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	16.02.2023 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक)	16.02.2023 (मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	16.02.2023 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	16.02.2023 (अपराह्न 01:30 से अपराह्न 03:30 बजे तक)	16.02.2023 (अपराह्न 04:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उप प्रधान के निर्वाचन-2023 हेतु ग्राम पंचायतों का विवरण-

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों में उप प्रधानों की संख्या
1	2	3	4
1	बहादुराबाद	80	80
2	भगवानपुर	54	54
3	रुड़की	45	45
4	नरसन	63	63
5	लक्सर	51	51
6	खानपुर	25	25
	योग-	318	318

राज्य निर्वाचन आयोग की उक्त अधिसूचना के क्रम में उ0प्र0 पंचायतीराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के नियम-117 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, विनय शंकर पाण्डेय, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) हरिद्वार, उक्त समय सारणी के अनुसार जिला हरिद्वार की समस्त ग्राम पंचायतों में उप प्रधान ग्राम पंचायत के निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के लिए दिनांक 16.02.2023 को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आमंत्रित करता हूँ। यह बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय के पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर आयोजित की जायेगी। उप प्रधान के निर्वाचन के लिये आवश्यक परिवर्तनों के साथ वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो ग्राम पंचायत में प्रधान पद के निर्वाचन के लिये लागू है। उप प्रधान पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने उनकी जांच नाम वापसी निर्वाचन चिन्ह आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी।

नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 10 फरवरी, 2023 से 15 फरवरी, 2023 तक (अवकाश दिवस को छोड़कर) पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक तथा दिनांक 16 फरवरी, 2023 को 08: बजे से 09:30 बजे तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत में निर्दिष्ट स्थान पर की जायेगी। नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री की सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा।

विनय शंकर पाण्डेय,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)
हरिद्वार।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 फरवरी, 2023 ई0 (माघ 29, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने अपना नाम शादी के उपरांत निर्मला से बदलकर निर्मला रावत कर लिया है भविष्य में मुझे निर्मला रावत पत्नी श्री यजुवेन्द्र कुमार रावत के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

निर्मला रावत पत्नी श्री यजुवेन्द्र कुमार रावत

निवासी 17-A, मंदाकिनी कॉलोनी एस.बी.आई.

बैंक के पास मोहनपुरा मोहम्मदपुर, रुड़की

जिला हरिद्वार।

कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद-रुद्रप्रयाग

विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली

उपविधि-2018

06 दिसम्बर, 2018 ई०

पत्रांक 413/न०५०ति०(उप०गज०न००)/2018-2019-

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-

क-यह उपविधि नगर पंचायत, तिलवाडा(रुद्रप्रयाग) "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि-2018" कहलायेगी।

ख- यह उपविधि नगर पंचायत, तिलवाडा(रुद्रप्रयाग) की सीमा में प्रवृत्त होगी।

ग- यह उपविधि नगर पंचायत, तिलवाडाद्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ-

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडासे है।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडाकी सीमाओं से है।

(ग) "अधिकाधिक अधिकारी" का तात्पर्य अधिकाधिक अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाडासे है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडाके अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडाके निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा प्रशासक से है।

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त)

संशोधन एवं उपान्तण आदेश-2002 से है।

(छ) "विज्ञापन" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडाकी सीमान्तर्गत प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन पर, होर्डिंग, बेनर पोस्टर एवं अन्य प्रचार सामग्री से है।

3. विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग/यूनिपोल) स्थल के अनुसार सड़कों के समानान्तर लगाये जायेंगे। छोटे यूनिपोल पेंटिंग सर्फेस से 2.5 मीटर की दूरी पर 5 × 3 फिट एवं सड़क से 8 फुट ऊँचाई पर होंगे। मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रांतीय मार्ग पर यूनिपोल के बीच कम से कम 30 फिट की दूरी होगी।

4. यूनिपोल/होर्डिंग सड़क से समानान्तर लगाये जायेंगे, जिससे यातायात सुगमता से संचालित हो सके एवं होर्डिंग के कारण सड़क दुर्घटना को न होने देने के उद्देश्य से जहाँ आवश्यकता होगी वर्षा से इन यूनिपोल/होर्डिंग को 25 डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सड़क के समानान्तर लगाने के निर्देश भी दिये जा सकते हैं।

5. होर्डिंग/यूनिपोल का अधिकतम साईज 20 × 10 फिट होगा।

6. होर्डिंग/यूनिपोल सड़क की पेंटिंग सर्फेस से न्यूनतम 2.5 मीटर दूरी पर लगाये जायेंगे।

7. होर्डिंग/यूनिपोल की संरचना मजबूत व फ्रेम के आकार की होगी चाहिये जिससे आंधी आदि में न गिरे। अतः इनकी संरचना के सम्बन्ध में स्ट्रक्चर इंजीनियर से रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

8. चौराहों व मोड़ों पर 25-25 मीटर दूरी तक होर्डिंग/यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।

9. प्रत्येक होर्डिंग के सम्बन्ध में सड़कवार एक यूनीक कोड नम्बर तय किया जायेगा जिसके विवरण में उस होर्डिंग का आकार प्रकार होर्डिंग विज्ञापन एजेन्सी का नाम लगाने का स्थान, स्वीकृति तिथि, रसीद नम्बर व उस होर्डिंग का सड़क से एंगल भी वर्णित किया जायेगा।

10. नगर पंचायत सीमा में विज्ञापन पट्ट लगाये जाने हेतु विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पट्ट लगाने से पूर्व नगर पंचायत कार्यालय में पंजीकरण कराया जायेगा। इस प्रकार केवल पंजीकृत एजेन्सियों को ही विज्ञापन पट्ट लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी। पंजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जायेगा।

11. नगर पंचायत, तिलवाडा में विज्ञापन एजेन्सियों को पंजीकृत किये जाने हेतु प्रथम बार पंजीकरण राशि ₹ 10,000.00 (दस हजार) पंचायत कोष में जमा करानी होगी। तत्पश्चात् पंजीकृत एजेन्सी अगले प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु ₹ 5,000/- (पाँच हजार) की धनराशि नवीनीकरण के रूप में नगर पंचायत कोष में जमा करायेगा।

12. नगर पंचायत सीमा में लगाये जाने वाले विज्ञापन पट्टों/पोल क्योरक का न्यूनतम शुल्क प्रति वर्ग फिट की दर से आगणित किया जायेगा। शुल्क निम्नानुसार होगा। प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी अथवा निम्न शुल्क को न्यूनतम मानते हुए होर्डिंग की सार्वजनिक नीलामी करायी जायेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	विवरण	दर (रु० में)	यूनिट
1.	मुख्य मार्ग (एन0एच0/प्रान्तीय मार्गों) के किनारे स्थित विज्ञापन/होर्डिंग्स (जो स्ट्रक्चर खड़ा कर लगाये गये हों)	130.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
2.	नगर पंचायत के मुख्य मार्ग एवं आन्तरिक गैहल्लों के सार्वजनिक स्थलों पर लगने वाले विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि	70.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
3.	इन्डीकैटर बोर्ड (आई0एच0पी0) (3×2 फिट) पोल व्योक्स 2 (3×2 फिट)	800.00	प्रति पोल/प्रतिवर्ष प्रति पोल/प्रतिवर्ष
4.	दुकानों/भवनों पर लगे ग्लोसाइन बोर्ड	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
5.	दुकानों/भवनों पर लगे साइन बोर्ड	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
6.	फलाईओवर कॉलम (10×20 फिट)	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
7.	पुल/पुल के कॉलम पर (10×20 फिट)	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
8.	प्रोटेक्शन स्क्रीम/नाला कवर्ट (8×15 फिट)	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
9.	निजी बस/पब्लिक बस एडवरटाइजिंग 4×15 फिट (दोनों साइड) बैंक साइड 3×3 फिट	40.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
10.	डिलवरी वाहन/सर्विस वाहन/टैक्सी	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
11.	डिमोस्ट्रेशन वाहन	400.00	प्रतिदिन
12.	बिल्डिंग सैप 80×20 फिट	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
13.	पार्किंग (दो डिसप्ले बोर्ड) 3×5 फिट	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
14.	ट्री-गार्ड 1.5×1.5 फिट	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
15.	ट्रैफिक बैरीकेटिंग	400.00	प्रति बैरीकेटिंग
16.	ट्रैफिक पोस्ट के ऊपर कियोरक 2×3 फिट	200.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
17.	सार्वजनिक शौचालय दो साइड वाल 8×10 फिट	200.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
18.	रोड डिवाइडर पर यूनिपोल गैन्ट्री 40×8 फिट	200.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
19.	लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार अतिरिक्त दिन के लिए	100.00 50.00	प्रतिदिन प्रतिदिन
20.	इवेंट एण्ड एकजीविशन/मेला एक दिन का अतिरिक्त दिन के लिए	8,000.00/800.0	प्रतिदिन
21.	स्थानीय केबल नेटवर्क पर प्रसारित विज्ञापनों पर शुल्क	80,000.00	वार्षिक
22.	बस शेल्टर 26×5 फिट	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
23.	बिजली/टेलीफोन के खम्बों पर 3×2 फिट	150.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
24.	बेलून (गुब्बारा) पर विज्ञापन	150.00	प्रति बेलून/प्रतिवर्ष

प्रतिबन्ध यह है कि मेला के दिन अथवा मेला होने लगने वाले विज्ञापन का शुल्क प्रतिदिन की दर से दुगुना लिया जायेगा।

3. निम्नलिखित क्षेत्रों को विज्ञापन की दृष्टि से विज्ञापन पट्ट प्रतिबन्धित रहेगा-

1-नदी के किनारे स्थित समस्त घाट।

2. धार्मिक स्थल।

3. नगर पंचायत कार्यालय के आसपास।

1. नगर पंचायत सीमान्तर्गत सम्प्रदर्शित किये जाने वाले ग्लोसाईन/साईन बोर्ड जो दुकानों के नाम के साथ या स्वतन्त्र रूप से किसी वस्तु के विषय, गुण आदि के बारे में उल्लेख हो, जनसाधारण को विज्ञापन की भांति आकर्षित करता हो, के विज्ञापनकर्ता से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी का कार्य निविदा के माध्यम से ठेके पर किया जायेगा।

विज्ञापन शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल तक पूर्णतः अग्रिम (100 प्रतिशत) जमा किया जायेगा। एक माह तक शुल्क जमा न होने पर सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा, तथा बकाया विज्ञापन शुल्क की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

इन्डिकेटर बोर्ड या अन्य बोर्ड जहां दोनों ओर विज्ञापन लिखे हों वहाँ निर्धारित शुल्क दुगुने हो जायेगा। इन्डिकेटर बोर्ड का साईज 5×3 फीट से अधिक का नहीं होगा।

विज्ञापन शुल्क नकद के रूप में ही जमा किया जायेगा।

निजी भवनों की छतों पर विज्ञापन पट्ट बिना नगर पंचायत की अनुमति के नहीं लगाये जायेगा।

प्रत्येक तिराहों एवं चौराहे में जहां कि समय-समय पर विज्ञापन पट्ट एकदम रास्ते के किनारे से एक दूसरे के अगल-बगल से आने वाले वाहनों का एक दूसरे को देखने में कठिनाई होती है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न होती है इन चौराहों एवं तिराहों में केन्द्र से चारों ओर पथों पर 25 मीटर तक विज्ञापन पट्ट लगाने में प्रतिबन्ध रहेगा।

पोल कियोरक का साईज 2×3 फीट होगा।

सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे-शराब, तम्बाकू, धूम्रपान एवं अश्लील, जातिसूचक, धार्मिक भवनाओं का उत्तेजित करने वाले, पशु क्रूरता, हिंसात्मक, विध्वंसक उत्पाद, हथियारों से सम्बन्धित उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

किसी भी विज्ञापन एजेन्सी द्वारा यदि स्वीकृत पट्ट के इतर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया गया, तो बिना केसी नोटिस के विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त के लिए कर एवं राजस्व अधीक्षक, नगर पंचायत, तिलवाड़ा स्वीकृत होर्डिंग का सत्यापन नियमित रूप से प्रतिमाह करेंगे।

विज्ञापन की स्वीकृति अधिकतम एक वर्ष के लिए दी जायेगी।

नहित अथवा यातायात की दृष्टि से एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पट्ट को हटाने आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट्ट हटा दिया जायेगा, जिस पर कोई प्रतिकर देय नहीं है।

यन रोड कांग्रेस द्वारा रोड साईन (आई0आर00सी0) 67-2001 में निर्धारित कलरों/मानकों का प्रयोग ही विज्ञापन के लिए अनुमत्य होगा। विज्ञापन पट्टों में प्रयोग किये जाने वाले रंग एवं फोन्ट साईज ऑफिशियल ट्रैफिक के समान एवं वाहन चालक को भ्रमित करने वाले नहीं होंगे।

न पट्ट/यूनिफोल का आवंटन विज्ञापन शुल्क के निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर सीलबन्द निविदाएँ आमन्त्रित कर बोलीदाता को किया जायेगा। निविदाएं मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा मठित समिति के द्वारा मांगी तथा उनका निर्णय अन्तिम एवं गान्य होगा।

1. निजी भवनों एवं भूमिओं पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगाने पर विज्ञापन एजेन्सी, ठेकेदार या स्वामी से रु0 30,000/- जुर्माना वसूल किया जायेगा एवं अवैध विज्ञापन पट्ट को तत्काल हटाने हुए एजेन्सी का पंजीकरण एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इस पर हाने वाले व्यय की वसूली विज्ञापन एजेन्सी पर से की जायेगी।

1. नगर पंचायत में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियों को जो भी विज्ञापन पट्ट स्वीकृत किये जायेंगे, उन पर सुन्दर स्वच्छ तिलवाड़ा का रसोगत प्रदर्शित किये जायेंगे तथा यातायात की दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा लगाये विज्ञापन के लिए होर्डिंग/यूनिफोल में उनकी आवश्यकतानुसार निःशुल्क स्थान दिया जायेगा।

29. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने बिना किसी नोटिस के एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए एजेन्सी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-299 (1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹0 5000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा मंग निश्चरण किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹0 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, तिलवाड़ा (रूद्रप्रयाग) में अन्तिम रूप में निहित होगा।

यह उप-नियमावली नगर पंचायत, तिलवाड़ा, जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) के प्रशासक की सहमति/विशेष प्रस्ताव के द्वारा पारित की गयी।

रविराज सिंह बंगारी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, तिलवाड़ा।

मंगेश घिल्डियाल,
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/
प्रशासक नगर पंचायत, तिलवाड़ा।

कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद—रूद्रप्रयाग

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण

उपविधि—2018

06 दिसम्बर, 2018 ई०

पत्रांक 413/न०५०ति०(उप०गज०न००)/2018-2019-

1- परिभाषा :

- (1) यह उपविधि नगर पंचायत, तिलवाडा (रूद्रप्रयाग) के ठेकेदारों को नियंत्रित एवं पंजीकरण उपविधि, 2018-19 कहलायेगी तथा गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।
- (2) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडा (रूद्रप्रयाग) से है।
- (3) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडा (रूद्रप्रयाग) के निर्वाचित अध्यक्ष/सभासदों से है।
- (4) "अधिनियम" का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 (यू०पी० म्यूनिसिपैलिटी एक्ट सं०-2, 1916 तथा संशोधित) जो कि वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश में भी लागू है—से है।
- (5) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडा (रूद्रप्रयाग) के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रशासक से है।
- (6) "अधिसासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत, तिलवाडा (रूद्रप्रयाग) से है।
- (7) "पंजीकरण" का तात्पर्य नगर पंचायत द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्य के ठेकेदारों के पंजीकरण से है।
- (8) "ठेकेदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/ फर्म से है जो नगर पंचायत, तिलवाडा (रूद्रप्रयाग) में समस्त निर्माण कार्य, सड़क/नाली, निर्माण, पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हों, को करने का इच्छुक है।
- (9) "श्रेणी" का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ (A.B.C.D) श्रेणी से है।

1- पंजीकरण की प्रक्रिया :

नगर पंचायत/पालिका परिषद के सड़क/नाली, पुस्तक एवं भवन के निर्माण कार्य के सम्पादन एवं सामग्री हेतु ठेकेदारों की चार श्रेणियाँ होंगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है :-

- (1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर सीमा, जनपद या उत्तराखण्ड प्रदेश में कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो। इसके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो व जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो कि छः माह की अवधि के अन्दर का हो देने अनिवार्य होंगे।

- (2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण-पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है) :-

(क) प्रथम श्रेणी के लिए	-	25.00 लाख
(ख) द्वितीय श्रेणी के लिए	-	12.00 लाख
(ग) तृतीय श्रेणी के लिए	-	5.00 लाख
(ग) चतुर्थ श्रेणी के लिए	-	2.00 लाख

- (3) प्रथम श्रेणी — प्रथम श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पालिका एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली एवं भवन निर्माण का 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में ₹ 50.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं की तकनीकी अभियन्ता एवं टी0एण्डपी0 मिक्सचर मशीन एवं बाईवरेटर आदि होने आवश्यक होंगे। (अनुभव प्रमाण-पत्र-अधिशाली अभियन्ता/अधिशाली अधिकारी/ अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा)।
- (4) द्वितीय श्रेणी — द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में ₹ 20.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे। (अनुभव प्रमाण-पत्र-अधिशाली अभियन्ता/अधिशाली अधिकारी/ अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा)।
- (5) तृतीय श्रेणी — तृतीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग में कम से कम से 1 वर्ष का कार्य किया गया हो, का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा।
- (5) चतुर्थ श्रेणी — चतुर्थ श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम से एक वर्ष का कार्य किया गया हो, का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा।
- (6) प्रत्येक ठेकेदार को आपकर व व्यापार कर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण प्रार्थना पत्र के साथ उक्त विभाग के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र देना होगा तथा पंजीयन नम्बर के अभिलेख की छायाप्रति देनी होगी।

3- पंजीकरण की अवधि :

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में माह 01 अप्रैल से 31 मई तक ही ठेकेदारों के पंजीकरण किये जा सकेंगे। पंजीकरण के निर्धारित प्रार्थना पत्र के प्रारूप को ₹ 200.00 पंचायत कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप पर मान्य होगा जो अवर अभियन्ता की आख्या पर अधिशाली अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात ही पंजीकरण शुल्क एवं जमानत-शुल्क जमा किया जायेगा। पंजीकरण की वैधता 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

4- जमानतें —

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में अधिशाली अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर प्रार्थना-पत्र के साथ देनी होगी :-

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए	—	₹ 30,000.00
(ब) द्वितीय श्रेणी के लिए	—	₹ 20,000.00
(स) तृतीय श्रेणी के लिए	—	₹ 12,000.00
(द) चतुर्थ श्रेणी के लिए	—	₹ 8,000.00

5- पंजीकरण शुल्क —

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क नकद रूप में नगर पंचायत कोष में जमा करना होगा :-

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए	—	₹ 15,000.00
(ब) द्वितीय श्रेणी के लिए	—	₹ 8,000.00
(स) तृतीय श्रेणी के लिए	—	₹ 4,000.00
(द) चतुर्थ श्रेणी के लिए	—	₹ 2,000.00

6- नवीनीकरण -

- (1) अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के कारण पंजीकरण/नवीनीकरण से रोका जा सकता है अथवा निरस्त किया जा सकता है।
- (2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र जिसका मूल्य रु0 200.00 होगा नगर पंचायत कार्यालय से क्रय कर विगत वर्ष किये गये कार्यों का विवरण देना होगा। ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार नवीनीकरण शुल्क नकद रूप में नगर पंचायत कोष में जमा करना होगा :-
- | | | | |
|-----|-----------------------|---|------------|
| (अ) | प्रथम श्रेणी के लिए | — | ₹ 6,000.00 |
| (ब) | द्वितीय श्रेणी के लिए | — | ₹ 4,000.00 |
| (स) | तृतीय श्रेणी के लिए | — | ₹ 2,500.00 |
| (द) | चतुर्थ श्रेणी के लिए | — | ₹ 1,500.00 |

7- निर्माण के सम्पादन की सीमा -

- प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगा --
- (1) प्रथम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।
- (2) द्वितीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ₹ 25.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।
- (3) तृतीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ₹ 10.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।
- (4) चतुर्थ श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ₹ 4.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकारी होंगे।

8- निविदा प्रपत्र का मूल्य -

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (अंशगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा :-

क्र.स.	कार्य की लागत (₹ मे)	निविदा मूल्य (₹ मे)
1	₹ 50,000.00 तक	200.00
2	₹ 50,001.00 से 2,00,000.00 तक	500.00
3	₹ 2,00,001.00 से 4,00,000.00 तक	800.00
4	₹ 4,00,001.00 से 20,00,000.00 तक	1500.00
5	₹ 20,00,001.00 से 50,00,000.00 तक	2500.00
6	₹ 50,00,001.00 से अधिक	4000.00

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य (बैट सहित) देकर खरीदेगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही अगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र नगर पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय किया जायेगा।

9- निविदा स्वीकार करने का अधिकार -

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी का होगा परन्तु किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रशासक को होगा। इस दशा में पुनः निविदायें आमंत्रित की जा सकती हैं। निविदा डालने के 6 माह बाद तक ठेकेदार उन्ही दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

10- धरोहर राशि -

निविदायें डालते समय 3 प्रतिशत धरोहर धनराशि प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को प्रतिभूति के रूप में जमा करनी आवश्यक है और यह प्रतिभूति अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक होगी। ऐसी प्रतिभूति को पूर्व के कार्यों में जमा प्रतिभूति के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा, जब तक कि उन्हें अवगुप्त नहीं किया गया हो।

11- ठेकेदार का भुगतान -

कार्य समाप्ति के पश्चात ठेकेदार को कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर, रायल्टी एवं जमानत की राशि काटने के उपरान्त कक्ष सभासद के कार्य सन्तोषजनक प्रमाण पत्र पर भुगतान किया जा सकेगा। जमानत राशि का भुगतान 1 वर्ष के बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जा सकेगा।

12- कार्य पूर्ण करने की अवधि -

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह टेण्डर फार्म में दी गई कार्य अवधि व अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेंट) के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करे। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया हो तो अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार अर्धदण्ड स्वरूप कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नहीं हो पाने की स्थिति में दण्ड की अवशेष धनराशि की कसूली भू-राजस्व के बकाये की गांति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी। इसका उल्लेख अनुबन्धनामे में भी आवश्यक रूप से किया जायेगा।

13- पंजीकरण निरस्तीकरण -

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीगेट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है या कार्य को किसी को सबलेट करता है तो ऐसी स्थिति में सभासद, अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को किसी भी समय निरस्त कर ठेकेदार को काली सूची में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत ठेकेदार के विरुद्ध जाँच में जमा किया गया कोई भी अभिलेख, अनुभव प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज यदि फर्जी पाये जाते हैं तो सम्बन्धित ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त कर किये जाने के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R) दर्ज करवा दी जायेगी। पंजीकरण के निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का भुगतान पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात किया जायेगा। इसका उल्लेख अनुबन्धनामे में भी किया जायेगा।

14- जमानत जब्त करने का अधिकार -

यदि ठेकेदार नगर पंचायत उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध-पत्र का उल्लंघन कर नगर पंचायत को कोई हानि पहुंचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त करने, ठेकेदार को काली सूची में सम्मिलित कर ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी नगर पंचायत की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी। इसका उल्लेख अनुबन्धनाम में भी किया जायेगा।

यह उप-नियमावली नगर पंचायत, तिलवाड़ा, जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) के प्रशासक की सहमति/स्वीकृति से विशेष प्रस्ताव के द्वारा पारित की गयी।

रविराज सिंह बंगारी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, तिलवाड़ा,
जनपद-रूद्रप्रयाग।

मंगेश घिल्डियाल,
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/
प्रशासक नगर पंचायत, तिलवाड़ा।

कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद-रुद्रप्रयाग

प्लास्टिक अवशेष (कचरा) प्रबन्धन एवं व्यवहार आदर्शउप नियमावली-2018

06 दिसम्बर, 2018 ई०

पत्रांक 413/न०प०ति०(उप०गज०न००)/2018-2019-

1- उपनियम

- (1) संक्षिप्त आगम एवं उत्पत्ति -पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट 1986 के अन्तर्गत प्लास्टिक कचरा अवशेष (प्रबन्धन एवं व्यवहार)नियमावली-2011 के नियम 4 (बी) के अन्तर्गत दी गई शक्तियों के अधीन नगर पंचायत,तिलवाडा (रुद्रप्रयाग) इस एक्ट के आधार पर सक्षम अधिकारी के तौर पर प्लास्टिक कचरे का प्रयोग, एकत्रीकरण, छटाई, उठान, निस्तारण व पुर्नचक्रण के लिए उपयुक्त विधायी शक्तियों का निर्वहन करेगी। उपयुक्त के अन्तर्गत नियमावली निम्न प्रकार होगी।

2- परिभाषा :

- (1) "कैरी बैग" का अर्थ प्लास्टिक की थैलियां जिन्हे उपयोग सामग्री के लिए प्रयोग में लाया जाता हो जिसमें स्वतः ले जाने योग्य लक्षण हों सहित
- (2) "कलरेन्टस्" वे रंगने वाले पदार्थ जो भारतीय प्रमाणिकता आई०एस० : 9833:1981 के अनुसार निर्धारित हों।
- (3) "एकत्रीकरण" का अर्थ प्लास्टिक कचरे को स्थायी एकत्रीकरण स्थल से अथवा अन्य किसी स्थान से उठाना व हटाना
- (4) "एकत्रीकरण स्थल" का अर्थ वह निर्धारित स्थान, शेड, किशोक या ढांचा जो म्यूनिसिपल या सरकारी जमीन,अथवा सार्वजनिक स्थान जहां प्लास्टिक कचरा प्राप्त करना व हटाना शामिल है।
- (5) "सामग्री" का अर्थ शाक सब्जियां, फल, दवाईयां, खाद्य सामग्री तथा इसी प्रकार की वस्तुएं साथ ही अन्य किसी भी प्रकार की वस्तुएं।
- (6) "कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक " का अर्थ यह है कि प्लास्टिक जो जैविक प्रक्रिया से कम्पोस्टिंग के दौरान C_{O_2} (कार्बन डाईआक्साइड) पानी, जैविक पदार्थों तथा बायोमास के सर्पक के दौरान अन्य सात कम्पोस्ट योग्य पदार्थों के भांति अनुकूल रहता है तथा कोई दृश्यमान अन्तर दर्शाने वाले तथा रसायनिक अवशेष नहीं छोड़ता है।

- (7) "पृथकीकरण" का अर्थ यह है कि पदार्थों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया।
- (8) "पर्यावरण" का अर्थ उन भौतिक व परिस्थितिकी से सम्बन्धित है जो जीवों के जीवन के विकास को प्रभावित करता है।
- (9) "उत्पादक की विस्तारित जिम्मेदारी"(EPR) का अर्थ है कि प्लास्टिक कैंरी बैग तथा बहुस्तरीय प्लास्टिक थैलियों की पैकिंग सामग्री के उत्पादक या निर्माता की वह जिम्मेदारी जिसके अन्तर्गत निर्मित प्लास्टिक सामग्री के समाप्त होने तक सामग्री का पर्यावरणीय प्रबन्धक सुनिश्चित हो। यह जिम्मेदारी उन सभी निर्माताओं पर भी लागू होती है जो इस प्रकार की पैकिंग सामग्री का उपयोग करते हैं।
- (10) "खाद्य सामग्री" का अर्थ वह सामग्री जो द्रव्य, ठोस व ठोस जैसी रूपों में तुरन्त खाने योग्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या बने हुए भोजन के रूप में हो।
- (11) "निर्माता" का अर्थ है वह व्यक्ति या संस्था जो प्लास्टिक कैंरी बैग, बहुस्तरीय पैकिंग सामग्री, पाऊच तथा या इसी प्रकार की सामग्री का पैकिंग के लिए उत्पादन करता हो।
- (12) "माइक्रोन" का अर्थ है प्लास्टिक फिल्म के मापन की इकाई जो एक मिलीमीटर के दशवें हिस्से के बराबर हो।
- (13) "बहुस्तरीय प्लास्टिक" का अर्थ है वह सामग्री जो पैकिंग हेतु कई स्तरों जैसे, कागज, गत्ते, पालीमर सामग्री या एल्मुमीनियम फॉयल की परतयुक्त या सम्मिलित रूप में हो।
- (14) "पिगमेंट" का अर्थ है एक रंगयुक्त पदार्थ अथवा तत्व है।
- (15) "प्लास्टिक" का अर्थ वह पदार्थ जिसमें उच्च पालीमर के तत्व विद्यमान हों तथा जो उसमें प्रसंस्करण प्रक्रिया में अन्तिम सामग्री के रूप में अपने स्वाभाविक रूप में रहे।
- (16) "प्लास्टिक कचरा" का अर्थ कोई प्लास्टिक कचरा जो कैंरी बैग, पाऊच या बहुस्तरीय पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग किया जाए व जिसे उपयोग के उपरान्त अथवा उनकी जीवनकाल के उपरान्त फेंक दिया जाए।
- (17) "प्रसंस्करण" का अर्थ कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें प्लास्टिक कचरे को उपचारित कर पुनः उपयोग हेतु बनाया जा सके।

- (18) "पुनर्चक्रीकरण" का अर्थ पृथकीकरण अजैविक प्लास्टिक कचरे को परिवर्तन प्रक्रिया के आधार पर नये उत्पाद के कच्चे माल के रूप में तैयार किया जाए, जो अपने मौलिक रूप में हो अथवा नहीं।
- (19) "पुनर्चक्रीकृत बैग" का अर्थ वह बैग जो उपयोग किये गये पालीमर या पूर्ववत् प्रसंस्कृत प्लास्टिक से बना हो।
- (20) "पृथकीकरण" का अर्थ वह म्यूनिसिपल ठोस कचरा जो जैविक व अजैविक कचरे, खतरनाक चिकित्सकीय, सूक्ष्म कचरा, निर्माण व तोड़ने से निकलने वाले कचरे, बाग व बगीचों का कचरा, तथा सभी तरह के कचरे।
- (21) "ढुलान" का अर्थ म्यूनिसिपल कचरे का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना।
- (22) "वर्जिन प्लास्टिक" का अर्थ वह प्लास्टिक जो पूर्व में उपयोग में नहीं लाई गयी हो अथवा किसी कचरे या अवशेष के साथ मिलाया न गया हो।
- (23) "अवशिष्ट प्रबन्धन" का अर्थ वैज्ञानिक आधार पर कम करना, दुबारा उपयोग, पुनर्चक्रीयण, कम्पोस्टिंग या प्लास्टिक कचरे का निस्तारण।
- (23) "वेस्ट पिकर" का अर्थ उन लोगों से है जो अकेले या समुदाय में रहकर प्लास्टिक अवशिष्ट का एकत्रीकरण करते हैं।

3- कैरी बैग तथा छोटे पाऊच आदि के स्टॉक, वितरण, विक्रय हेतु निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक :

- (अ) कैरी बैग प्राकृतिक रंग (रंग रहित) जिसमें कोई रंग तत्व न हो या भारतीय प्रमाणिकता : आई एस : 9833:1981 के अनुसार वैधानिक रंग तत्वां द्वारा निर्मित हो।
- (इ) किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे कैरी बैग जो पुनर्चक्रित प्लास्टिक या कम्पोस्ट किये जाने वाले प्लास्टिक से बने हों, को खाद्य पदार्थों के स्टोर लाने ले जाने, विवरण या पैकिंग के लिए प्रयोग में लाया जाए।
- (व) किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी कैरी बैग का उत्पादन, स्टोर वितरण या विक्री नहीं किया जा सकता है। जो 40 माइक्रोन की मोटाई से कम हो या वर्जिन पुनर्चक्रीकरण या कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक से न बना हो।

- (क) कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक बर्तन जो भारतीय प्रमाणिकता आई0एस0/आई0एस0ओ0 17088 जो समय-समय पर संशोधन के आधार पर कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक के लिए निर्धारित किये गये हैं।

4- प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन निम्नानुसार हो :

- (अ) प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रणीयण, पुनः प्राप्त करना, निस्तारण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों, प्रावधानों व प्रमाणिकता के अनुसार किया जाना होगा।
- (इ) नगर पंचायत, तिलवाड़ा (रूद्रप्रयाग) कचरा प्रबन्धन के संचालन तथा समन्वयन के लिए निम्न सम्बद्ध गतिविधियाँ संचालित करेंगे :
- (i) प्लास्टिक कचरे का सुरक्षित एकत्रीकरण, स्टोर, पृथकीकरण, ढुलान, प्रसंस्करण, तथा निस्तारण।
 - (ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रसंस्करण के दौरान पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो।
 - (iii) यह सुनिश्चित करना कि यदि सम्भव हो तो प्लास्टिक कचरे के एकत्रीकरण केन्द्र के निर्माण में निर्माता को भागीदार बनाना।
 - (iv) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रण करने वाली संस्थाओं के साथ निरन्तरता स्थापित करना।
 - (v) जागृति कार्यक्रमों से इससे जुड़े सभी सम्बद्ध इकाईयों को उनकी जिम्मेदारियों का ज्ञान बढ़ाना।
 - (vi) कचरा प्रबन्धन में जुड़ी सभी संस्थाओं या समूहों(कूड़ा बीनने वालों सहित) को जोड़ना।
 - (vii) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक को खुले में न जलाया जाना।
 - (viii) जबकि एकत्रीकरण व्यवस्था की जिम्मेदारी म्यूनिसिपैलिटी की है तथा इस उद्देश्य के लिए वह प्लास्टिक कैंरी बैग, बहु स्तरीय प्लास्टिक पाऊच या थैलियाँ, प्लास्टिक बोतलें, प्लास्टिक तिरपाल, शीतल पेय वस्तुएँ आदि के निर्माताओं या ब्रांड मालिक जो इनका उपयोग करते हैं की सहायता ले सकती है।
 - (i) यह म्यूनिसिपैलिटी प्लास्टिक कचरे के विसंक्रमण के लिए श्रीनगर विसंक्रमण व परतीकरण इकाई जो उत्तराखण्ड टूरिज्म डेवेलपमेन्ट बोर्ड

द्वारा संयोजित है तथा गढ़वाल रेंज के शहरी स्थानिक संस्थाओं के विकास के लिए है तथा प्लास्टिक प्रसंस्करण व पुनर्चक्रणीय इकाई काठगोदाम जो झील विकास प्रधिकरण नैनीताल द्वारा कुमांऊ क्षेत्र के शहरी स्थानिक संस्थाओं हेतु चलाई जा रही है। के साथ समन्वय करेगी।

5- विपणन या चिन्हीकरण हेतु प्रयास :

(1) प्रत्येक प्लास्टिक कैरी बैग का बहुस्तरीय पाऊच या थैली में निम्न सूचना अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में प्रिंट करना आवश्यक होगा।

- (i) निर्माता का नाम व रजिस्ट्रेशन संस्था तथा कैरी बैग की स्थिति में उसकी मोटाई।
- (ii) बहुस्तरीय प्लास्टिक पाऊच या थैली में निर्माता का नाम व रजिस्ट्रेशन संख्या।
- (iii) सभी पुनर्चक्रीकृत कैरी बैग में "पुनर्चक्रीकृत" लिखा हुआ या चिन्हित हो जो भारतीय प्रामाणिकता : आई0एस0: 14534:1998. के अनुसार निर्मित हो।
- (iv) सभी वे कैरी बैग जो कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक हों में "कम्पोस्ट योग्य" लिखा हुआ या चिन्हित हो तथा भारतीय प्रामाणिकता के अनुसार निर्मित हो।
- (v) सभी खुदरा व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी प्लास्टिक कैरी बैग तथा बहुस्तरीय पाऊच या थैलियां जो उनके द्वारा बेचे जाएं, में नियमानुसार चिन्हित हों।

6- इसके अतिरिक्त कोई भी कैरी बैग खुदरा व्यापारियों द्वारा क्रेताओं को निःशुल्क उपलब्ध नहीं होना चाहिए। कैरी बैग का न्यूनतम मूल्य कैरी बैग की गुणवत्ता व आकार के अनुसार हों जो उसके निर्माण सामग्री तथा कचरा प्रबन्धन की लागत भी शामिल हो। जिससे प्लास्टिक कचरा संवर्धन में कमी करने को बढ़ावा दिया जा सके। कैरी बैग की कीमत जो क्रेताओं से ली जाए ₹ 1/- से कम न हो।

7- इसके अतिरिक्त म्यूनिसिपैलिटी समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो जाँच कर सकेगी।

8- यू0पी0 प्लास्टिक तथा अन्य अजैविक कूड़े(उपयोग का विधान व निस्तारण) एक्ट 2000 के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा फेंके गये अजैविक बैग या डिब्बों के द्वारा निम्न स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं :

- (i) नालियों व सीवर लाइन व्यवस्था में व्यवधान पैदा होना
- (ii) नालियों व सीवर के उदभवों की निरन्तरता व निस्तारण व उपचार में व्यवधान उत्पन्न होना।
- (iii) जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक व लोक कन्टक का कारण हो सकता है।
- (iv) म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय सौन्दर्य के लिए खतरा या नुकसान का कारण बन सकता है।
- (v) सभी खुदरा व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी प्लास्टिक कैंरी बैग तथा बहुस्तरीय पाऊच या थैलियां जो उनके द्वारा बेचे जाएं, में नियमानुसार चिन्हित हों।

उक्त सभी खतरों के लिए एकट नियमावली के प्रावधान संख्या 8 के अनुसार दण्डनीय अपराध है। उसी के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

यह उप-नियमावली नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद-रुद्रप्रयाग(उत्तराखण्ड) के प्रशासक की सहमति/स्वीकृति से विशेष प्रस्ताव के द्वारा पारित की गयी।

रविराज सिंह बंगारी,
अधिसासी अधिकारी,
नगर पंचायत, तिलवाडा,
जनपद-रुद्रप्रयाग।

मंगेश धिल्डियाल,
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग/
प्रशासक नगर पंचायत, तिलवाडा।

कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद—रूद्रप्रयाग
लाइसेंस शुल्क निर्धारण एवं संग्रह

उपविधि—2018

06 दिसम्बर, 2018 ई०

पत्रांक—413/न०प०ति०(उप०गज०न००)/2018-2019—

- 1- यह उपविधि नगर पंचायत, तिलवाडा जनपद—रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) के सीमान्तर्गत विभिन्न एवं निजी स्तर से संचालित व्यवसायों पर लागू होगी एवं यह उपविधि लाइसेंस शुल्क निर्धारण एवं संग्रह उपविधि, सन् 2018 कहलायेगी।
- 2- परिभाषा : नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद—रूद्रप्रयाग से है।
 - (1) “अधिनियम” का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 (यथा संशोधित यू०पी० म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, 1916) जो कि वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश में भी लागू है—से है।
 - (2) “अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडा(रूद्रप्रयाग) के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रशासक से है।
 - (3) “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत, तिलवाडा(रूद्रप्रयाग) से है।
 - (4) “लाइसेंस” से तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 294 व 298 की उपधारा (2) के अन्तर्गत शुल्क निर्धारण सम्बन्धी उपविधियों के अधीन उल्लिखित एवं विभिन्न व्यवसायों को वर्गीकृत अनुसूची में वर्णित व्यवस्था व दरों से है तथा विभिन्न व्यवसायों के संचालन हेतु दी जाने वाली स्वीकृति से है।
 - (5) “अवधि” लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। लाइसेंस वित्तीय वर्ष के किसी भी माह में जारी किया जाए, लाइसेंस अवधि 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी।
 - (6) “अनुसूची” से तात्पर्य इस उपविधि में वर्णित व्यवसायों एवं लाइसेंस शुल्क की दरों से है।

- (7) यदि कोई व्यवसाय एक से अधिक वर्गीकृत व्यवसाय श्रेणी में माना जा सकता हो, तो अनुसूची में जिस श्रेणी में अधिक दर से लाइसेन्स शुल्क चिह्नित किया गया हो, उसी के अनुसार उस व्यवसाय पर लाइसेन्स शुल्क लगाया व वसूला जायेगा।
- (8) व्यवसाय से सम्बन्धित श्रेणी/ विवरण (मद) के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 3- लाइसेन्स आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज) देनी होगी तथा आवेदन में व्यवसाय / विवरण का उल्लेख भी करना होगा।
- 4- प्राप्त आवेदन पत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा समुचित विचारोपरान्त लाइसेन्स दिये जाने / न दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा। न दिये जाने की सूचना का कारण भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
- 5- अनुसूची में वर्णित व्यवसायों से सम्बन्धित व्यवसाय द्वारा लाइसेन्स 1 अप्रैल से 31 मई तक की अवधि के भीतर बना लिया जाना अनिवार्य होगा।
- 6- लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च (1 वित्तीय वर्ष) तक वैध होगा। अन्यथा स्थिति में विलम्ब शुल्क (जो लाइसेन्स शुल्क का 10 प्रतिशत से कम न होगा), लाइसेन्स अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा व अतिरिक्त अधिभार के रूप में जमा करना होगा।
- 7- लाइसेन्स धारक अपना व्यवसाय यदि बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय में अपने पुराने लाइसेन्स विवरण के साथ लिखित रूप से उपलब्ध करायेगा।
- 8- लाइसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी अधिकारी में निहित होगा।
- 9- जांचकर्ता की जांच के समय व्यवसाय से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व व्यवसायी का होगा।
- 10- लाइसेन्स अधिकारी स्वयं अथवा अपने ऐजेंसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य सम्पादित करा सकता है।
- 11- उक्त अनुसूची में वर्णित लाइसेन्स सम्बन्धी नियम-उपनियमों का उल्लंघन होने अथवा पाये जाने की दशा में लाइसेन्स अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाइसेन्स निरस्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में लाइसेन्स अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील प्रस्तुत करता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष में निहित होगा।
- 12- नगर पंचायत, तिलवाड़ा, जनपद-रूद्रप्रयाग में इन उपविधियों/नियम-उपनियमों के तहत वर्तमान में प्रचलित विभिन्न लाइसेन्स उपविधियां उस सीमा तक, जो इस नियमावली के लिए असंगत होगी, वे निरस्त समझी जायेंगी।

- 13- जिन विषयों के सम्बन्ध में इन उपविधियों में कोई उप नियम नहीं होगा उन विषयों में अधिशासी अधिकारी स्वविवेक अनुसार निर्णय ले सकता है ऐसा निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 14- अधिशासी अधिकारी समय-समय पर ऐसे प्रपत्र भी निहित कर सकता है, जो इन उपविधियों के सम्यक् पालन के लिए आवश्यक हो।

अनुसूची

क्र. सं.	विवरण (मद)	निर्धारित दरें
1	होटल लॉज 10 बेड तक	1000.00
2	होटल लॉज बडे 10 बेड से अधिक	2000.00
3	गैस्ट हाऊस	1000.00
4	रेस्टोरेन्ट	1000.00
5	नर्सिंग होम	5000.00
6	पैथोलॉजी सेन्टर	1500.00
7	एक्स रे सेन्टर	2000.00
8	डेंटल क्लीनिक	1500.00
9	मेडिकल स्टोर	2000.00
10	मोटर गैरेज	800.00
11	स्कूटर गैरेज/रिपेयरिंग शाप	600.00
12	पेट्रोल पंप/डीजल पंप, आयल कंपनी	5000.00
13	चक्की	600.00
14	ड्राईक्लीनर	1000.00
15	फर्नीचर की निर्माता/	1200.00
16	फर्नीचर शोरूम/दुकान	2500.00
17	हार्डवेयर/लोहा व्यापारी, सीमेंट, ईट	4500.00
18	बिजली के सामान की दुकान	1800.00
19	कपड़ा व्यापारी/कपडे की दुकान	2500.00
20	टेंट एवं कैटरिंग	1500.00
21	बेकरी (भट्टी)	1000.00
22	बेकरी (बिजली)	1500.00
23	ब्यूटी पार्लर	1500.00
24	कुकिंग गैस ऐजेंसी	5000.00
25	जनरल मर्चेन्ट	800.00
26	टेलरिंग हाऊस 1 मशीन	300.00
27	टेलरिंग हाऊस 3 मशीन तक	700.00
28	टेलरिंग हाऊस 3 से अधिक	1500.00
29	ज्वैलर्स	4000.00
30	डेयरी	600.00
31	केबिल नेटवर्क	1000.00
32	आडियो एवं वीडियो लाइब्रेरी	800.00
33	एकाउन्टेंट, कन्सलटेन्ट आदि	2000.00

34	फाइनेन्स कम्पनी, चिटफंड आदि	3500.00
35	इन्शोरेंस कम्पनी प्रति शाखा	4500.00
36	मांस विक्रेता(बकरा/मुर्गा)	2000.00
37	विदेशी शराब की दुकान	25000.00
38	पान की दुकान	600.00
39	चाय की दुकान	600.00
40	किताबों की दुकान स्टेशनरी	1500.00
41	लकड़ी का टाल	1000.00
42	रेडियो/टी0वी0/घड़ी/मोबाइल रिपेयरिंग	600.00
43	रेडियो/टी0वी0/मोबाइल की दुकान/शो रूम	2000.00
44	बर्तन/क्राकरी/प्लास्टिक सामान की दुकान	1500.00
45	मिठाई की दुकान	1000.00
46	घाट/बताशा/ की दुकान	500.00
47	सब्जी और फल की दुकान छोटी	800.00
48	सब्जी और फल की दुकान बड़ी थोक	2000.00
49	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	3000.00
50	चूड़ी/कास्मेटिक आदि	1000.00
51	फोटोग्राफर	700.00
52	बारातघर	5000.00
53	प्राइवेट स्कूल	3500.00
54	रेडिमेन्ट गारमेट्स	1800.00
55	कबाड़ी	2500.00
56	कम्प्यूटर कोचिंग	2500.00
57	कम्प्यूटर जाब वर्क	1000.00
58	स्पेयर पार्ट्स के दुकान	800.00
59	खाने का होटल	800.00
60	ढाबा	800.00
61	हेयर ड्रेसर	1000.00
62	ऑप्टिकलस	700.00
63	वाहन शोरूम(सेल्स सर्विस)	4000.00
64	परचून	1200.00

यह उप-नियमावली नगर पंचायत, तिलवाड़ा, जनपद-रूद्रप्रयाग(उत्तराखण्ड) के प्रशासक की सहमति/स्वीकृति से विशेष प्रस्ताव के द्वारा पारित की गयी।

रविशज सिंह बंगारी,
अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत, तिलवाड़ा,
जनपद-रूद्रप्रयाग।

मंगेश घिल्डियाल,
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/
प्रशासक नगर पंचायत, तिलवाड़ा।

कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा जनपद—रुद्रप्रयाग नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि—2018

06 दिसम्बर, 2018 ई0

पत्रांक 413/न0प0ति0(उप0गज0न00)/2018-2019—

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ:—

1. यह उपविधि नगर पंचायत, तिलवाडा की 'नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, "2018" कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पंचायत, तिलवाडा के समस्त क्षेत्रों में प्रभावी होंगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

4. परिभाषाएँ:—

- a) "उपविधि" से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है।
- b) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडा के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- c) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडा के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा प्रशासक से है।
- d) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपात्तरण आदेश-2002 से है।
- e) "नगर पंचायत" से तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडा से है।
- f) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर नगर तिलवाडा से है।
- g) "सफाई निरीक्षक" से तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडा (रुद्रप्रयाग) में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है। ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पालिका/नगर पंचायत के उस अधिकारी/कर्मचारी से है जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या प्रशासक या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।
- h) "निरीक्षक अधिकारी" का तात्पर्य मुख्य अधिशासी अधिकारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है जिन्हें समय-समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया हो।
- i) "नियम" से तात्पर्य भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000 व पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की अधिसूचना सं0 861 नई दिल्ली, शुक्रवार अप्रैल, 8, 2016 बनाये गये ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 व अधिसूचना सं0 197 दिनांक 28 मार्च, 2016 से है।
- j) "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड, नगर पालिका अधिनियम से है।
- k) "जीव नाशित/जैव निम्नकरणीय/जैविक अपशिष्ट" (Biodegradable waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है जैसे-बचा हुआ खाना सब्जी-फल के छिलके फूल-पौधों के पत्ते आदि।
- l) "जीव अनाशित अपशिष्ट" (Non-Biodegradable waste) का तात्पर्य ऐसे कूड़ा-कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा-कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।
- m) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट" (Recyclable waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो दुबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा किसी विधि से परिवर्तन उपरान्त प्रयोग में आ सकता हो जैसे-प्लास्टिक, पॉलिथीन, कागज, धातु, रबड़ आदि।
- n) "जैवचिकित्सीय अपशिष्ट" (Biomedical waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रिया कलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ है।
- o) "संग्रहण" (Collection) से तात्पर्य अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।
- p) "कचरा खाद बनाने" (Composting) से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्फलित है।
- q) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" (Demolition and Construction Waste) से सन्निर्माण, पुन निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट अभिप्रेत है।
- r) "व्ययन" (Disposal) से भूजल सतही जल तथा परिवंशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।
- s) "अपशिष्टों के उत्पादक" (Generator of Waste) से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है।
- t) "भूमिभरण" (Landfilling) से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उठने वाले धूल हवा के साथ उड़ने वाला बदबू आग के खतरे, पक्षियों का खतरा नाशी जीव/कृत्तक ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमिभरण पर निपटान अभिप्रेत है।
- u) "निक्षालितक" (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है।

- v) "नगर पालिका प्राधिकारी" (Municipal Authority) से म्युनिसिपल कार्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर पंचायत जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, सीमित (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।
- w) "स्थानीय प्राधिकारी" (Local Authority) का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत से है।
- x) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" (Municipal Solid Waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्साकीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।
- y) "सुविधा के परिचालक" (Operator of a Facility) से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण भी आता है जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन के लिए नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है।
- Z) "पुन चक्रण" (Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तित करता है, जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।
- aa) "पृथक्करण" (Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग-अलग करना अभिप्रेत है।
- bb) "भण्डारण" (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थायी रूप से इस प्रकार ढिब्बा बन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा-करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवाय पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।
- cc) "परिवहन" (Transportation) से विशेष रूप से डिजायन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन कराना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट बिखरने रोग वाहकों की पहुंच से रोका जा सके।
- 5- कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क नाली, फुटपाथ किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका/नगर पंचायत इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित नहीं किया गया है न डालेगा और न डलवायेगा।
- 6- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा जिनमें से एक में जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।
- 7- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त विन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पालिका के द्वारा निर्धारित समय प्रक्रिया के अनुसार नगर पालिका के कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक (Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरों जो समय-समय पर संशोधित की जा सकेंगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) लिये जायेंगे।
- 8- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पालिका/नगर पंचायत से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा।
- 9- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़-पौधों के कूड़े को परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां ऐसा सम्भव न हो नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करेगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।
- 10- नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार-द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक को देना होगा।
- 11- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों को प्रबन्धन जीव-चिकित्सा अपशिष्टों (प्रबन्धन और हस्तन) नियम, 1988 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।
- 12- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न जलवायेगा।
- 13- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन पृथक्करण, संग्रहण भण्डारण, परिवहन तथा व्यय से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।
- 14- निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर पाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठवाने की आवश्यकता समझी जाती है जो मासिक यूजर चार्ज के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पालिका/सुविधा के प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्ज वसूल किया जा सकेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी। यह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगर पालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

- 15- अनुसूची में दी गयी दरों में द्विवार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जिसकी गणना ₹ 5/- के पूर्णांक में की जायेगी।
 16- उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्ज में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

अनुसूची-1 सेवा शुल्क (User Charges)

क्र० सं०	अपशिष्ट एवं अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की राशि ₹0 में			
		जैविक अजैविक कूड़ा अलग-अलग कर सड़क तक पहुँचाने पर	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक-अजैविक कूड़ा घर/स्रोत पर ही अलग-अलग देने पर	जो व्यक्ति घर/स्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा दें
1	गरीबी रेखा से नीचे के घर (बी.पी.एल. कार्ड धारक)	—	05	10	15
2	कम आय वाले घर (बी.पी.एल. कार्ड धारक के अतिरिक्त 5000 प्रतिमाह तक आय)	05	10	15	20
3	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	10	20	25	30
4	होटल/लाजिंग/गेस्ट हाउस (20 बेड तक)	250	350	450	550
5	होटल/लाजिंग/गेस्ट हाउस (20 बेड से अधिक)	450	550	750	1000
6	धर्मशाला	10	25	40	50
7	बरातघर	500	750	950	1150
8	बेकरी	100	200	150	300
9	कार्यालय	50	75	100	150
10	सब्जी एवं फल विक्रेता	100	200	100	125
11	रेस्टोरेन्ट (छोटे)	150	250	350	500
12	रेस्टोरेन्ट (बड़े)	250	400	500	750
13	स्कूल कॉलेज एवं आवासीय शिक्षण संस्थायें	100	200	200	200
14	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम	200	400	200	250
15	मेडिकल स्टोर	150	250	100	125
16	दुकान (चाय व छोटी)	50	75	100	150
17	दुकान (बड़ी शोरूम आदि)	100	150	250	350
17	वर्कशॉप/कबाड़ी	300	500	350	750
18	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150
19	मांस एवं गछली विक्रेता	100	150	200	300
20	क्लीनिक/पैथोलॉजी	100	150	200	300
21	वर्कशॉप	100	150	200	300
22	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	250	350	450	650

अनुसूची-2 अपशिष्टों की श्रेणी

जैविक (Biodegradable)
 हर प्रकार का पका, बिना पका हुआ खाद्य अपशिष्ट
 सब्जी एवं फलों के छिलके, फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा
 घरेलू झाड़ू से निकली गन्दगी
 सेनिटरी टॉवल
 बच्चों के डायपर

पुनः चक्रणीय (Recyclable)
 कागज तथा हर प्रकार का प्लास्टिक
 कार्ड बोर्ड तथा कार्टन
 हर प्रकार की पैकिंग
 हर प्रकार के डिब्बे (परिसंक्रमण को छोड़कर)
 हर प्रकार का कांच/धातु/रबड़/तकड़ी
 फाईल, पुडिया, ट्रेटपैक, कैसेट, कम्प्यूटर, डिस्कट, इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्ज, खराब कपड़े फर्नीचर आदि

घरेलू परिसंक्रमण (Hazardous)
 एरोसोल कैन

बटन सेल, फ्लेशलाइट/कार बैटरी

ब्लीच घरेलू रसाई तथा नाली सफाई का सामान
 ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद
 रसायन तथा उनके खाली डिब्बे, सौन्दर्य प्रसाधन तथा उनके खाली डिब्बे
 इन्जेक्शन, सुई तथा सिरिज, खराब दवाईया, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे

लाईट बल्ब, द्युब लाईट तथा छोटे फ्लोरोसेन्ट बल्ब
 थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद
 पेन्ट, तेल, गोंद, धीनर तथा उनके डिब्बे फोटोग्राफी के रसायन।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि के किसी भाग का उल्लंघन करने पर नगर पंचायत/नगर पालिका अर्धदण्ड वसूल कर सकेगी जो सेवा शुल्क की निर्धारित दरों का 10 गुना तक अधिकतम हो सकता है। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन, नियम-2016 के उल्लंघन पर रु0 200 प्रति घन मी0 की दर से अर्धदण्ड वसूल किया जायेगा। निरन्तर उल्लंघन की दशा में रु0 500 प्रति घन मी0 प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा।

यह उप नियमावली नगर पंचायत तिलवाड़ा जनपद-रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) के प्रशासक जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग की सहमति पर दिनांक 27/08/2018 के द्वारा पारित की गयी।

रविराज सिंह बंगारी,
अधिसासी अधिकारी,
नगर पंचायत, तिलवाड़ा।

मंगेश धिल्लियाल,
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/
प्रशासक नगर पंचायत, तिलवाड़ा।